₹ 10

www.kewalsachtimes.com

अप्रैल 2026

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay paytm

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

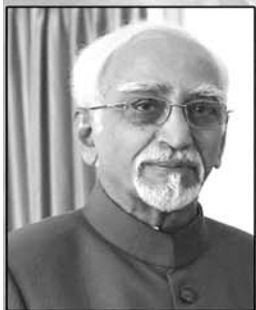

मो० हामिद अंसारी
01 अप्रैल 1937

अजय देवगन
02 अप्रैल 1969

प्रभु देवा
03 अप्रैल 1973

जया प्रदा
03 अप्रैल 1962

जितेन्द्र
07 अप्रैल 1942

रामगोपाल वर्मा
07 अप्रैल 1962

अल्लु अर्जुन
08 अप्रैल 1983

जया बच्चन
09 अप्रैल 1948

जयराम रमेश
09 अप्रैल 1954

मणिशंकर अय्यर
10 अप्रैल 1941

टैरेंस लेविस
10 अप्रैल 1975

स्व० सतीश कौशिक
13 अप्रैल 1956

मुकेश अंबानी
14 अप्रैल 1957

मंदिरा बेदी
15 अप्रैल 1972

लारा दत्ता
16 अप्रैल 1978

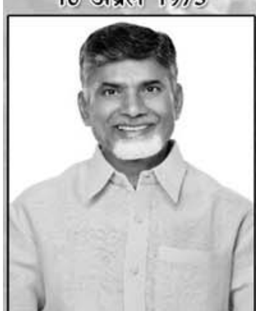

एन. चंद्रबाबू नायडू
20 अप्रैल 1950

चेतन भगत
22 अप्रैल 1974

मनोज बाजपेयी
23 अप्रैल 1969

सचिन तेन्दुलकर
24 अप्रैल 1973

आशिष नेहरा
29 अप्रैल 1979

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

''सर से सरक जाये उसको सलवार कहते हैं, और जो घोषणा करके मुकर जाये उसको सरकार कहते हैं।'' झूठ बोलना और उसको सच साबित करने के लिए विपक्ष पर दोष मढ़ना ही राजनीति है और राजनीति में अपने वायदे से मुकर जाना ही जुमला कहलाता है। विदेशों से कालाधन आयेगा? गाय नहीं कटेगी, 15 लाख खाते में, अबकी बार-मोदी सरकार के नारे के साथ 2014 में गुजरात के लाल नरेन्द्र मोदी को भारत की जनता ने PM चुनकर स्पष्ट बहुमत से सदन भेजा। 2019 के चुनाव फिर 2024 के चुनाव हुए और इन चुनावों में अबकी बार मोदी की सरकार के बजाय नारा बदलकर ''**फिर एकबार-मोदी सरकार**'' जुमला बनता चला गया। धर्म एवं विकास की राजनीति की दुहाई देते हुए ना खाउंगा और न खाने दूंगा का नारा को भी पिछले 12 वर्षो में जुमला करार दे दिया गया। पिछले 15 वर्षो की राजनीति को गौर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भारत देश में लोकतांत्रित मूल्यों का घोर पत्तन हो गया और शब्दों की मर्यादा भी तार-तार हो गई। किसी को माँ-बहन की गाली भी जुमले का रूप लेने लगी। भारत हिन्दूराष्ट्र बनते-बनते, विश्वगुरू बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है और 2047 में बनेगा की तिथि देने वाले स्वयं 2047 में रहेंगे! की बात भी जुमले जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जुमलेबाजी के खेल में सिर्फ मोदी सरकार सफल है बल्कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी इसी खेल में मशगूल है और पकड़े जाने पर जुमला है कहकर फिर से जनता के उम्मीदों के साथ खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ''अब नहीं सहेंगे जुमलों का वार, अब नहीं बनेगी मोदी सरकार'' जनता सबकुछ समझ चुकी है और अपना निर्णय लेगी।

जन्म से मृत्यु तक सिर्फ

जुमला

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

जनता को आजादी के पूर्व भी वही हालत थी और आजादी के बाद भी वही है क्योंकि आंख मूंदकर किसी भी नेता की गलत बात को मानकर समाज में प्रचार करने लगता है। सवर्णों को आरक्षण की पहली शर्त है संविधान संशोधन, इसकी पहली जरूरत है दो-तिहाई बहुमत इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो पाएंगे कि मोदी जी ने एक और जुमला फेंका है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग वर्षों से चल रही है। मोदी ने अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) शुरू की। इस पहल का उद्देश्य 15 करोड़ परिवारों के लिए बैंक खाते और डेबिट कार्ड बनाना, उन्हें 5,000 रुपये (52 अमेरिकी डॉलर) तक का ओवरड्राफ्ट और दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना था। योजना शुरू होने के बाद जनवरी 2015 तक 125.4 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। आज जनधन योजना के तहत खोले गये खाते की स्थिति क्या है, पर गंभीरता से मंथन करने पर जुमला जैसा ही प्रतीत होता है। नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद जनता से सीधे संवाद करने के लिए भारत के सरकारी संवाद माध्यम ऑल इंडिया रेडियो का सहारा लिया और ''मन की बात'' नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। मन की बात से क्या लाभ हुआ? जबकि मन की बात सिर्फ भाजपा के कार्यकर्त्ता एवं पदाधिकारी हीं सुनते हैं। पीएम मोदी के इस कदम का देश को क्या फायदा मिला है इसकी गणना करना किसी भी राजनीति पंडित के लिए बड़ी चुनौती है। 08 नवंबर 2016 की रात अचानक टीवी पर आए और घोषणा कर दी कि देश में चल रहे 1000 और 500 रुपये के नोट उसी रात 12 बजे से चलन से बाहर हो जाएंगे। सरकार ने दावा किया कि इस कदम से देश में छिपा काला धन सामने आ जाएगा। 10 साल नोटबंदी के पूर्ण हो गये लेकिन कालाधन का कोई हिसाब आज तक सार्वजनिक नहीं हो सका। नोटबंदी के वक्त दावा किया गया था कि नोटबंदी ने आतंकवादियों की जड़े हिला देगी परन्तु लगातार कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ने लगे। नोट बदलने के चक्कर में बैंक के अंदर और लाइन में लगे कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोगों के रोजगार भी चले गए। खुद पीएम मोदी की वृद्ध माँ भी लाईन में लगी। सरकार ने दावा किया भारतीय सेना ने पाक सीमा में घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक की और कई आतंकी ठिकानों सहित आतंकियों को मार गिराया। कहा गया कि इस ऑपरेशन ने भारत-पाक सीमा में बने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूत कर दिया है लेकिन इसके बाद से कश्मीर और पंजाब में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पिछले 10 साल से सत्ता में रही डॉ० मनमोहन सरकार पर ये आरोप लगाती रही कि उसकी पाकिस्तान नीति पूरी तरह से विफल है। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की यात्राएं की और ये प्रचार किया गया कि इससे भारत पाकिस्तान को घेरने में कामयाब हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक गलियारा बनाए जाने के मामले पर भारत के सभी पड़ोसी देशों ने चीन के पक्ष में खड़े होकर भारत को ही अलग-थलग कर दिया। **स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे सहित कई** मामले जुमले की तरह दिखने लगे हैं। पिछले कई वर्षों में संसद के सत्रों में जिस प्रकार के शब्दों का बौछार पक्ष एवं विपक्ष एक दूसरे के प्रति इस्तेमाल करते हैं जिससे आमजनता के बीच गलत संदेश जाता है। संसद में अब कई शब्दों के बोले जाने पर रोक लगा दी गई है। इन शब्दों में जुमलाजीवी, तानाशाह, चोर, बेशर्म और घड़ियाली आंसू भी शामिल हैं। इसके अलावा बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट, विश्वासघात, भ्रष्ट, नाटक, पाखंड और अक्षम जैसे शब्दों को भी असंसदीय करार दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता लगातार करते रहे हैं आज उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वे शब्द असंसदीय हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि तोलाबाज को तोलाबाज कहते हैं और जुमलेबाज को जुमलेबाज कहा जाएगा। रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी कहा कि अगर कुछ शब्दों को लेकर कानून में बदलाव करना है तो उसकी परंपरा यह है कि सभी दलों के नेताओं से बातचीत की जाती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने टीवी कैमरे पर एक बार कहा था कि चुनाव में हम जो कहते हैं वह जुमले होते हैं तो हमने जुमलेबाज शब्द कहा, ऐसे में यह कहां से असंसदीय हो गया। आईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर वह कहेंगे कि वह मोदी सरकार पर फूल बरसा कर मारेंगे क्योंकि उसने नौजवानों को बेरोजगार किया है तो क्या फूल शब्द को असंसदीय करार दे दिया जाएगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई बुकलेट के मुताबिक, अराजकतावादी, शकुनी, तानाशाही, तानाशाह, जयचंद, विनाश पुरूष, खालिस्तानी, खून से खेती जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल संसद में बहस के दौरान होने पर इन्हें संसद की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के लिए किसी भी हद तक जाकर जुमलेबाजी कर सकती है और कोई सरकार 2500 तो कोई 10000 देकर सरकारी खजाना खाली कर रही है। सत्ता लेने के लिए किसी भी प्रकार का वादा करके सत्ता प्राप्त करना और इसके बाद उसको पूरा करने के वक्त जुमला कह देना आदतों में शुमार हो चुका है।

KEWAL SACH TIMES

A National Magagzine

वर्षः- 15, अंकः- 178 माहः- अप्रैल 2026 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.–14,

मकान संख्याः- 14/28, कंकड़बाग, पटना–800020 (बिहार)

सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

मार्च 2026

हत्या

मिश्रा जी,

दिल्ली के पत्रकार संजय कुमार सिन्हा ने मार्च 2026 के अंक में दिल्ली की खूनी होली त्यौहार पर सांप्रदायिक हत्या में तरुण खटीक की मौत एक कमजोर कर रहे सनातन संस्कृति व्यवस्था का परिणाम माना जा सकता है की बात को पूरी गंभीरता के साथ खबर को लिखा है। आपसी झगडे को लेकर तरुण खटीक के बीच दोस्ती के आड़ में साम्प्रदायिक दंगे का रूप कैसे ले लिया के विषय पर पुरे मामले की तहकीकात के साथ लिखा जाना मजबूत पत्रकारिता का परिचय है। संजय सिन्हा की दूसरी खबर केजरीवाल बंगले के रिनोवेशन पर CAG रिपोर्ट पर तीखी बहस में भी पुरे मामले की पड़ताल की है।

● **सुजीत पाठक, रेलवे कॉलोनी, इंदौर एम.पी**

एक पर एक

संपादक महोदय,

मार्च 2026 अंक में कई खबरें दिल को दहला देने वाली है जिसको पढकर काफी चिंता होती है। मध्यप्रदेश के इंदौर में हुए **''लोगों की दर्दनाक मौत''** की खबर को पढ़कर ऐसा महसूस हुआ की आलिशान मकान और आधुनिक सुरक्षा की वजह से इतनी दर्दनाक मौत हुई. भीषण आग और धमाके की आवाज ने पुरे कॉलोनी को दहला दिया। बिजली के उपकरण का शार्ट सर्किट होने की वजह से बम धमाका जैसा माहौल बन गया. प्रशासन चाहकर भी मदद नहीं कर क्योंकि सुरक्षा के कारण बचाव दल अंदर समय पर नहीं पहुंच सका। आपकी यह खबर पढ़कर मन में डॉ भी पैदा हो गया की आधुनिक सुरक्षा भी मौत का कारण बनी।

● **महेन्द्र पाल सिंह, करोल बाग, नई दिल्ली**

चुनावी महासंग्राम

मिश्रा जी,

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के घोषणाओं के आधार पर के सटीक विश्लेषण किया गया है। मार्च 2026 अंक में केवल सच टाइम्स पत्रिका ने TMC - BJP के बीच चल रहे राजनीतिक युद्ध पर वोटरों को किसके पक्ष में मतदान करना है बंगाल के चुनाव में सत्ता पर काबिज हो उसका उल्लेख करके लिखा जाने वाला अजित दुबे का खबर चुनावी महासंग्राम पढ़ने योग्य है। केवल सच टाइम्स पत्रिका के मार्च अंक में प्रकाशित सभी खबरें एक से बढ़कर एक है। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच मंचों से ब्यानबाजी हुई और हिन्दुओं को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है।

● **संजय पासवान, मानपुर बाजार, गया**

नाथेंगे

संपादक महोदय,

आपका संपादकीय सरकार एवं समाज को आइना दिखाने का काम करता है और सरल भाषा में अपनी लेखनी से सबकी आँखे भी खोल देता है। मार्च अंक 2026 का आपका संपादकीय सबको नाथेंगे एक साथ आदित्यनाथ में 2027 के चुनाव सहित भाजपा की नाव के खेवनहार भी योगी हीं बनेंगे की बात आपकी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस प्रकार IAS संतोष वर्मा के विवादस्पद बयान पर साथ दे रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार की UGC 2026 कानून ने भी देश के अंदर गृहयुद्ध की स्थिति बना दी है पर सटीक समीक्षात्मक आलेख को प्राथमिकता के साथ लिखा है।

● **मनोहर सिन्हा, अस्सी घाट, बनारस, यूपी**

नाराज ब्राह्मण

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के मार्च 2026 अंक में प्रकाशित वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना की खबर बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों पर सभी दलों का दाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोटरों को पक्ष में करने के लिए, खासकर ब्राह्मणों का एकतरफा वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन घोषणा कर रही है। UGC 2026 का काला कानून से नाराज सवर्णों को अपने पक्ष में करने के प्रयास पर सटीक समीक्षा की है तो संजय सक्सेना की दूसरी खबर आजम का समय खराब तो अखिलेश का नए चेहरे पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। 125 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा को ब्राह्मण वोटर हीं किसी को सत्ता की सिंहासन पर विराजमान करा सकता है।

● **रौशन सिंह, अशोक नगर, नई दिल्ली**

नासिक का आशिक

ब्रजेश जी,

मैं केवल सच टाइम्स द्विभाषीय पत्रिका का नियमित पाठक हूं। मार्च 2026 अंक में गुड्डू कुमार सिंह की खबर नासिक का आशिक में अशोक खरात के विषय में बहुत ही सटीक जानकारी के साथ खबर को लिखा है और पाठकों को बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार पूजा पाठ तंत्र मंत्र के नाम पर पदाधिकारी एवं कारोबारी यजमान के साथ गलत कार्य को अंजाम देता था। महाराष्ट्र सरकार भी इस काले कारनामे से हैरत में है। तंत्र-मंत्र के नाम पर उनके पति के मौत का डर दिखाकर अवैध संबंध बनाने वाला अशोक खरात की काली करतूत सबके सामने सार्वजनिक हो चुकी है। इस प्रकार की खबरों से जानकारी तो मिलती है।

● **पंकज चटर्जी, बाबू बाजार, कोलकात्ता, पं.बं.**

अन्दर के पन्नों में

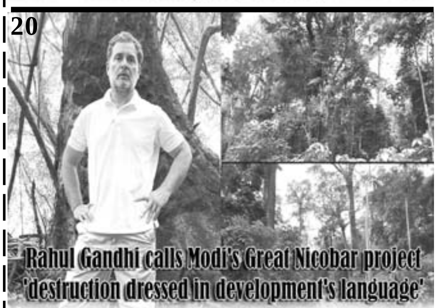

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी

'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☛ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☛ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 20001817444
BANK :- State Bank Of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 || 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

घायल हूं इसलिए घातक हूं

● संजय कुमार सिन्हा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत 6 अन्य सांसदों ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये। इसके बाद से आम आदमी पार्टी नेताओं के बयान आना शुरू हो गये। बता दें कि पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया है। वही सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अन्ना हजारे ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। किसी के विचारों को दबाना सही नहीं है। लोकतंत्र में अलग-अलग सोच और मत होना स्वाभाविक है। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, यही कारण है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि संविधान में किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर किसी को कहीं और जाना है तो वह जा सकता है। लेकिन अगर पार्टियां सही तरीके से काम करें और अंदरूनी अनुशासन बनाए रखें, तो ऐसी स्थिति

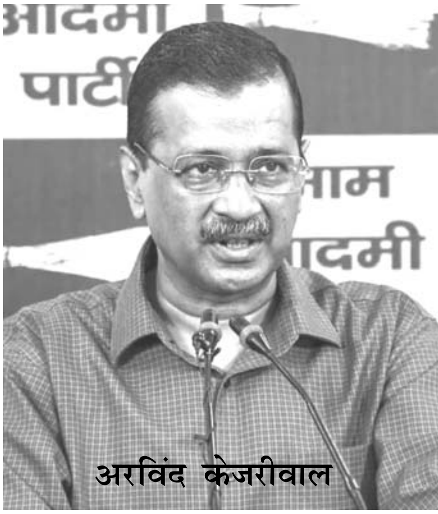
अरविंद केजरीवाल

अन्ना हजारे

संजय सिंह

पैदा ही नहीं होती कि लोग पार्टी छोड़ें। दूसरी तरफ 'आप' सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने उस पार्टी के साथ विश्वासघात किया जिसने उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाया।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के बनने से लेकर अब तक का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 'स्वराज' और 'भ्रष्टाचार विरोध' के नारे के साथ शुरू हुई इस पार्टी से समय-समय पर कई बड़े चेहरे अलग हुए। कुछ ने वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ी, तो कुछ को अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल दिया गया। अब आप नेता राघव चड्ढा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके साथ 6 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी है। उनके साथ आम आदमी पार्टी के अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी आदि बीजेपी में शामिल हो गये। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल का 'मैं' पड़ा 'आप' पार्टी पर भारी, तो फिर क्यों बिछड़ गए सभी बारी-बारी। यह सिलसिला

अभी शुरू नहीं हुआ बल्कि इनकी कतारे पुरानी है जिनमें पहला नाम योगेंद्र यादव का है। पार्टी के मुख्य रणनीतिकार और 'थिंक टैंक' माने जाते थे। 2015 में उन्हें और प्रशांत भूषण को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर कर दिया गया। उन्होंने बाद में 'स्वराज इंडिया' बनाई। इसके बाद नाम आता है प्रशांत भूषण का। मशहूर वकील और लोकपाल आंदोलन के स्तंभ। अरविंद केजरीवाल के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाने के बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद नाम आता है आनंद कुमार का। जेएनयू के प्रोफेसर और प्रमुख बुद्धिजीवी, जो योगेंद्र यादव के साथ ही पार्टी से अलग हुए। इसके बाद कुमार विश्वास का नाम आता है। पार्टी के सबसे लोकप्रिय वक्ताओं और संस्थापक सदस्यों में से एक। राज्यसभा टिकट न मिलने और नेतृत्व के साथ अनबन के चलते वे धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और बाद में पार्टी से उनके रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। अब वे रामकथा और कृष्ण कथा बांचते हैं। इसके बाद नाम आता है आशुतोष का। पूर्व पत्रकार और पार्टी के अहम प्रवक्ता। 2018 में उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, हालांकि चर्चा राजनीतिक मतभेदों की थी। इन कतारों में नाम एच.एस. फुल्का का भी है। पंजाब में पार्टी का बड़ा चेहरा और सिखों के मुद्दों पर मुखर

योगेन्द्र यादव

प्रशांत भूषण

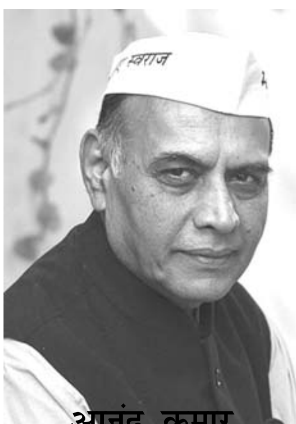
आनंद कुमार

कुमार विश्वास

आशुतोष

एच.एस. फुल्का

सुखपाल सिंह खैरा

कपिल मिश्रा

रहने वाले वकील। उन्होंने 2019 में राजनीति और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नाम है सुखपाल सिंह खैरा का। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। नेतृत्व से मतभेदों के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वही अभी भाजपा के कद्दावर नेता कपिल मिश्रा का नाम भी इस सूचि में आता है। ये दिल्ली सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद संदीप कुमार का नाम आता है। राशन कार्ड विवाद के बाद उन्हें मंत्री पद से हटाया गया और बाद में वे पार्टी से अलग हो गए। कैलाश गहलोत का नाम भी इसमें आता हैं। नवंबर 2024 में दिल्ली सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश गहलोत ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका माना गया। इसके बाद नाम आता है राज कुमार आनंद का। ये दिल्ली सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने ईडी की छापेमारी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पार्टी छोड़ दी। बता दें कि शाजिया इल्मी पार्टी की एक प्रमुख आवाज थीं, लेकिन नेतृत्व शैली से असंतोष के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में बीजेपी में शामिल हो गईं।

राघव चड्ढ़ा

विदित हो कि पार्टी छोड़ने से पहले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर अपने अकाउंट के माध्यम से एक नया वीडियो जारी कर पार्टी की ओर से किए जा रहे सामूहिक राजनीतिक आरोपों का करारा जवाब दिया था। उन्होंने वीडियो का शीर्षक 'घायल हूं इसलिए घातक हूं' रखा था। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। 3 आरोप, एक भी सच नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक स्क्रीप्टेड कैम्पेन चलाया जा रहा है। पहले मैंने सोचा कि इन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा लेकिन फिर मुझे लगा कि एक ही झूठ सौ बार बोला जाता है तो कुछ लोग सच न मान लें। इसीलिए मैं यह जवाब दे रहा हूं। राघव चड्ढा ने कहा कि यह कोई इत्तिफाक नहीं है कि आप के कई नेताओं की ओर से कमोबेश एक ही तरह के आरोप लगाकर उन्हें घेरा जा रहा है। गौरतलब है कि आप ने राघव चढ्डा के स्थान पर अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता बनाया था। इसके बाद से ही पार्टी में घमासान मचा हुआ था। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि मुझे जब-जब संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे मुद्दे उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। राघव चड्ढा ने सवाल किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता की

संदीप कुमार

कैलाश गहलोत

राज कुमार आनंद

शाजिया इल्मी

समस्याओं पर बात करना कोई अपराध है? वही आम आदमी पार्टी में मची तोड़फोड़ पर 'आप' सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आपने भगवंत मान के कार्यों को रोकने का जो काम किया है, उसके लिए आपको पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज पंजाब जैसी अच्छी सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके ऑपरेशन लोटस का तंत्र चलाया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस और राजनीति का खेल जिसमें भगवंत मान के कार्य रोकने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब की सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है। पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो तो 10 लाख रुपए तक का इलाज कराने का काम किया जाता है। ऐसी सरकार को भाजपा ने रोकने और तोड़ने का काम किया है। 'आप' राज्य सभा के 7 सांसद अलग होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। इन सातों नामों को पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी। राघव चड्ढा को 'आप' ने क्या नहीं दिया लेकिन वे भाजपा में चले गए। इन सभी नेताओं को 'आप' ने जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता को धोखा

संसद में राघव चढ्ढा

दिया है।

बहरहाल, 'आप' के 7 सांसदों का विलय भाजपा की ऊपरी सदन में ताकत बढ़ाएगा। इससे महत्वपूर्ण विधेयकों पर समर्थन मिलने में मदद हो सकती है, खासकर जब INDIA गठबंधन को तोड़ने के प्रयास चल रहे हों। चड्ढा जैसे चेहरों का आना भाजपा की विस्तारवादी छवि को मजबूत कर सकता है। हालांकि यह घटना भाजपा के लिए सकारात्मक प्रतीत होती है, लेकिन लोकसभा में हालिया महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल 2026 की पराजय ने सरकार की चुनौतियों को उजागर किया है। यह बिल महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने और परिसीमन से जोड़ने का प्रयास था। लोकसभा में इसे दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला (लगभग 298-230 के आसपास वोट पड़े, लेकिन आवश्यक बहुमत नहीं जुटा) और बिल गिर गया। विपक्ष (खासकर दक्षिणी दल जैसे DMK, TMC) ने इसे "ट्रोजन हॉर्स" बताया। महिला आरक्षण के नाम पर उत्तरी राज्यों (भाजपा के मजबूत क्षेत्र) को ज्यादा सीटें देने की कोशिश। इससे भाजपा की महिला सशक्तिकरण की छवि को नुकसान पहुंचा और संघीय ढांचे पर सवाल उठे। यह मोदी सरकार की लोकसभा में एक बड़ी विधायी हार मानी जा रही है, जो दिखाती है कि संख्या बल के बावजूद व्यापक सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में, 7 सांसदों का आना राज्यसभा में अल्पकालिक राहत दे सकता है, लेकिन लोकसभा में बिल पास कराने या 2029 की रणनीति (परिसीमन पर निर्भर) के लिए पर्याप्त नहीं। जनता के मुद्दों जैसे महंगाई, रोजगार और क्षेत्रीय

असंतुलन पर विपक्ष की एकता अभी बनी हुई है। अल्पकालिक बढ़त, लेकिन रणनीतिक सबक राघव चड्ढा और 7 सांसदों का भाजपा में जाना मोदी सरकार को अल्पकालिक फायदा जरूर देगा, राज्यसभा में मजबूती। 'आप' को कमजोर करना और "विपक्ष टूट रहा है" का नैरेटिव। लेकिन महिला आरक्षण-परिसीमन बिल की हार याद दिलाती है कि लोकसभा में संख्या के साथ-साथ सहमति भी जरूरी है। राजनीति में ऐसे विलय अक्सर व्यक्तिगत फैसले या दबाव का नतीजा होते हैं। लंबे समय में जनता तय करती है कि कौन सही दिशा में है। भाजपा को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन बिना आत्मसंतोष के। क्योंकि विकास, शासन और सहमति के मुद्दों पर विपक्ष अभी पूरी तरह हारा नहीं है।

बहरहाल, ये जो सात सांसदों ने 'आप' छोड़ 'भाजपा' में शामिल हुए, ये कभी 'आप' के नूर थे। अरविंद केजरीवाल की आंखों के कोहिनूर थे। इनमें कोई आपका चाणक्य बनकर सियासी चाल चल रहा था तो कोई धन्ना सेठ बनकर पार्टी की सांस चला रहा था। किसी को केजरीवाल का अगला वारिस कहा जा रहा था। कोई राज का

संजय सिंह

नरेन्द्र मोदी

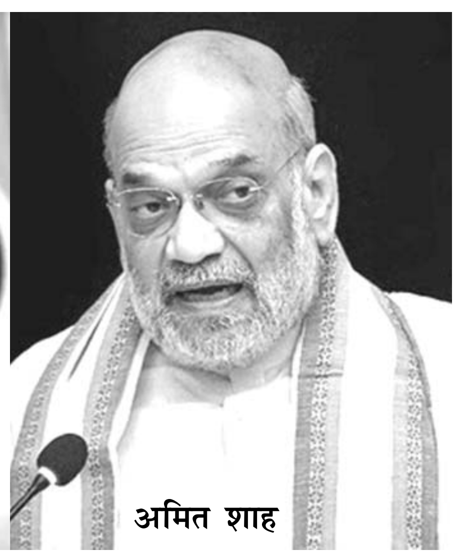
अमित शाह

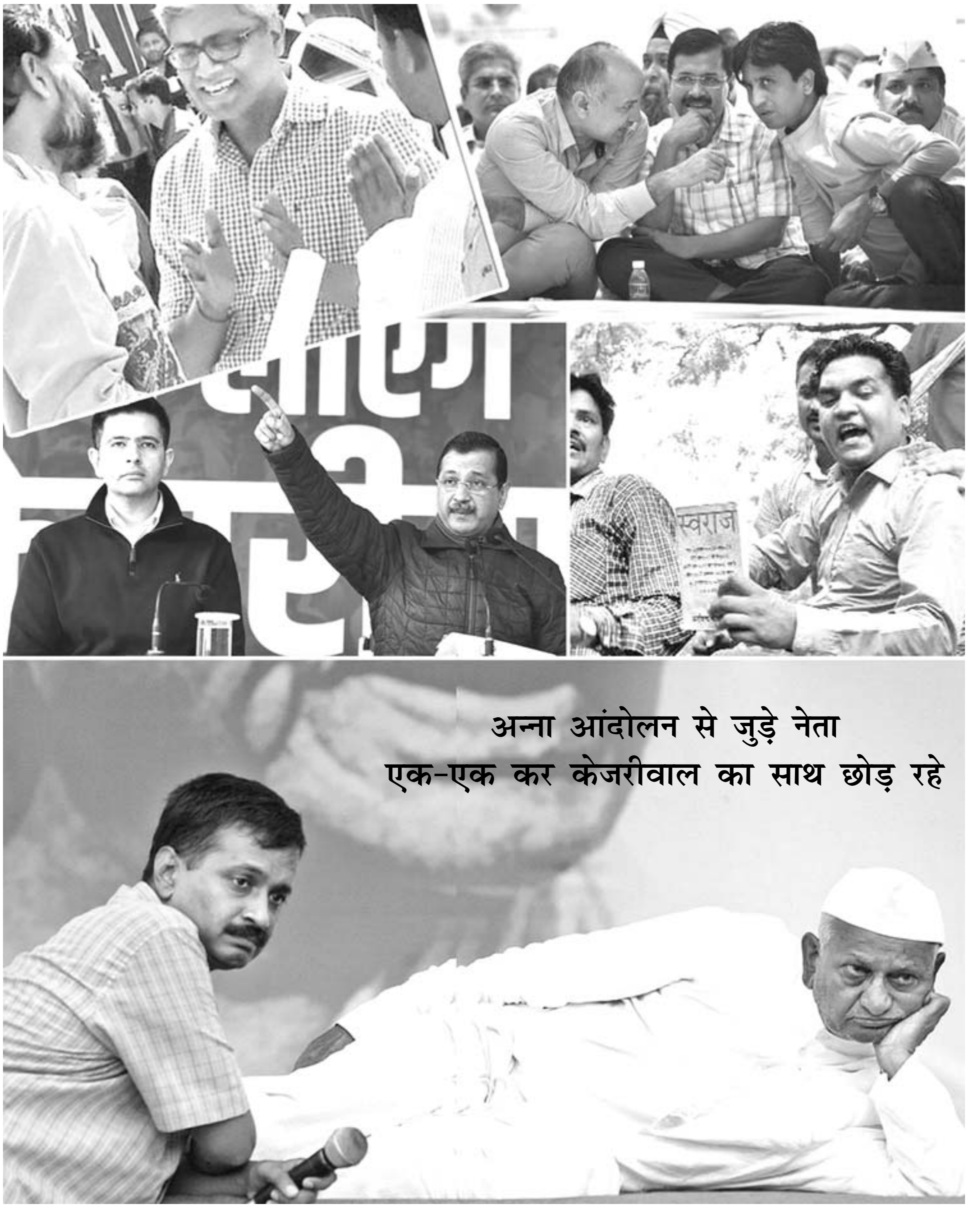

अन्ना आंदोलन से जुड़े नेता एक-एक कर केजरीवाल का साथ छोड़ रहे

सबसे गहरा ताला था। किसी के पास इतना डाटा था कि उसने पंजाब जीता दिया था तो कोई केजरीवाल के साथ कदमताल करते हुए आंदोलन से पार्टी और पार्टी से राज्यसभा पहुंच चुका था। लेकिन आज यही चेहरे सियासत के दरबार में पाला बदल चुके हैं। हैरानी कुछ को है कि ये क्यों चले गए? कुछ इस बात से हैरान हैं कि इतनी देर तक कैसे टिक गए? कुछ इस बात को लेकर सवाल उठा रहे कि जो लोग सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने निकले थे। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। वो सिस्टम के गोद में बैठकर सत्ता का सुख कैसे भोग रहे हैं? दरअसल यह कहानी आम आदमी के खास आदमी और खास आदमी से विभीषण और कुछ की नजरों में गद्दार बनने की है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह कहानी एकतरफा है तो गुरु ये सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये सिर्फ पार्टी के टूटने की कहानी नहीं है। ये एक विचार की लाश है। एक आंदोलन की खुली हत्या है। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ एक जौहरी हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने दावा किया था कि अन्ना आंदोलन की मिट्टी से वो तमाम हीरे तराश रहा है। चुन-चुन के ऐसे नायाब लोगों को ला रहा है जो देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। वो भी कह रहे थे। दूसरी तरफ वही हीरे जिन्हें कभी केजरीवाल ने तराशा था, राज्यसभा भेजा था, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ संघर्षों में दिन रात खड़े थे। आज वो हीरे केजरीवाल के पांव में चुभ रहे हैं। अब सवाल क्या हुआ का नहीं है। सवाल यह है कि गलती कहां हुई? क्या यह अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ अहंकार था, जिसने केजरीवाल के अपनों को ही दुश्मन बना दिया? क्योंकि ये कहानी यहां से तो शुरू होती नहीं। याद कीजिए अन्ना आंदोलन। किरण बेदी से लेकर शशि भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास। बड़ी लंबी कतार है। आशुतोष से लेकर अब राघव चड्ढा तक। सवाल है कि केजरीवाल का अहंकार था या फिर डर, दबाव और लालच जिसने इन चेहरों को बिकने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये जितने हैं, इनमें से अधिकतर की पहचान तो पहली बार बनी थी, केजरीवाल से बनी थी। आखिर ये क्यों केजरीवाल से दूर चले गए? इतिहास कहता है केजरीवाल के साथ कोई ऐसा बचा ही नहीं, जो उनका सगा रहा। लेकिन जब हर मोहरा एक-एक करके बोर्ड छोड़ दे तो शख्श सिर्फ मोहरों पर नहीं होता, खिलाड़ी पर भी जाता है और असली सवाल यही है कि गद्दारी ज्यादा बड़ी है या उसे पहचानने में हुई चूक। क्योंकि जब जौहरी ही हीरो और पत्थरों में फर्क करना भूल जाए तो बगावत खबर नहीं बनती, नतीजा बन जाती है और आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की। यह कहानी है बगावत की। यह कहानी है भरोसे के टूटने की, एक आंदोलन के सपने दिखाने की और उन सपनों के राख बनने की। सिस्टम को बदलने वाले सिस्टम का हिस्सा बनने की।

आखिर हुआ क्या कि रातोरात आम आदमी पार्टी का पूरा किला ढह गया। क्योंकि कल तक जो पार्टी राज्यसभा में अपनी ताकत के दम पर केंद्र को चुनौती दे रही थी, आज उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का वजूद खतरे में है। हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर बगावत की। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दल-बदल कानून की बारीकियों को इतनी सफाई से इस्तेमाल किया गया कि दो तिहाई बहुमत के साथ पार्टी का विलय कर लिया। अब किसी की सदस्यता पर कोई आंच नहीं है। यानी ये सब के सब जो है ये राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। इस बगावत का चेहरा बने राघव चड्ढा, मास्टर माइंड बने संदीप पाठक, इनके साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सहानी, राजेंद्र गुप्ता

और स्वाति मालीवाल ने मिलकर केजरीवाल के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खींच ली। अब ये केवल एक इस्तीफा थोड़ी था। यह तो एक सोची समझी अरविंद केजरीवाल पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेखबर थे और बेखबर से ज्यादा यह स्ट्राइक उनके सबसे कमजोर वक्त में उन पर एक बड़े प्रहार के तौर पर थी। लेकिन जब इस पूरी बगावत की आप गहराई में जाते हैं तो सुई जो है वो घूम फिर कर केजरीवाल पर आकर टिकती है। राजनीति में अक्सर यह मुहावरा दोहराया जाता है कि 'राजा वही जो सबको साथ लेकर चले'। लेकिन केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहां राजा के साथ रहने की एक्सपायरी डेट छोटी है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक ये लिस्ट चीख चीखकर गवाही दे रही है।

अब यहां दो पक्ष आमने-सामने तलवार ताने खड़े हैं। पहला पक्ष कहता है कि केजरीवाल का अहंकार जो है उस ऊंचाई पर है जहां पर संवाद की जगह सिर्फ आदेश बचे हैं। मान लो तो टिके हो, नहीं मान रहे हो तो साइड लाइन कर दिए जाओगे। हर बढ़ता हुआ कद केजरीवाल को अपनी कुर्सी के लिए खतरा लगने लगता है।

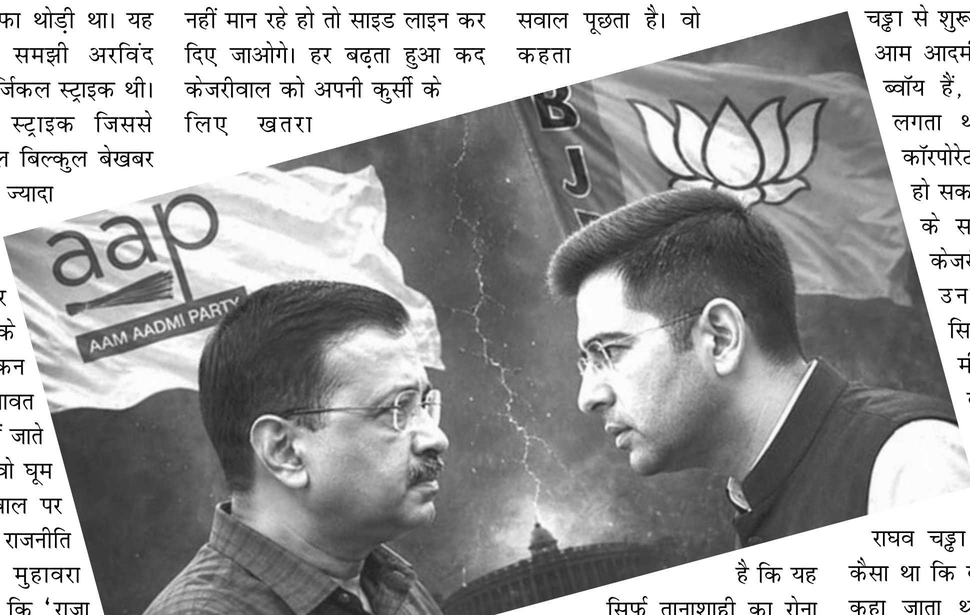

कुमार विश्वास ने कहा था कि वो एक नया लड़का हेरोइन से शादी कर लिया है। आजकल वायरल रहता है। राजनीति के चक्कर में है लेकिन उसकी राजनीति खतरे में है क्योंकि केजरीवाल का नंबर दो बन रहा है और नंबर दो केजरीवाल को पसंद नहीं। अब सवाल है की क्या यह नेतृत्व की वो तानाशाही है जिसने वफादारों के हाथ में बगावत का झंडा फहराया? हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है। वो भी उतना ही तीखा सवाल पूछता है। वो कहता है कि यह सिर्फ तानाशाही का रोना है या फिर सीबीआई और ईडी की फाइलों का खौफ। क्योंकि केजरीवाल के साथ जितने नेता थे वो जेल गए और जो जेल नहीं गए, वो विदेश चले गए। आंख का इलाज करवाने। क्या वो ईडी, वो सीबीआई, वो फाइल उनका डर है कि नेताओं ने पाला बदल लिया? क्या निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन लोगों ने उस आदमी के साथ विश्वासघात उसके सबसे कमजोर समय में किया, जिसने इन लोगों को राजनीति का ककहरा पढ़ाया था। क्योंकि आए तो थे ये क्रांतिकारी बनकर, लेकिन अब बीजेपी के दरबार में गए हैं दरबारी बनकर। जनता भी देख रही है कैसे एक आंदोलन के नाम पर बनाई गई पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां वफादारी की शर्त केजरीवाल जी की जी हुजुरी है। लेकिन सवाल आज केजरीवाल और उस जौहरी पर है जिसने हीरा परखने में नहीं बल्कि सहेजने और उन पर भरोसा करने में गलती कर दी। क्योंकि हीरे तो थे ही, तभी सबने नाम कमाया। स्वाति मालीवाल ने नाम कमाया, राघव चड्ढा ने नाम कमाया। लेकिन हीरों का जौहरी आज अकेला खड़ा है और वो अपने किले के मजबूत स्तंभों को एक-एक कर उखड़ता हुआ देख रहा है और उसकी शुरुआत की जो बड़ी कहानी है वो राघव चड्ढा से शुरू होती है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वो पोस्टर ब्वॉय हैं, जिन्हें देखकर कभी लगता था कि राजनीति में कॉरपोरेट क्लास और विजन हो सकता है। अन्ना आंदोलन के समय से राघव चड्ढा, केजरीवाल की परछाईं थे। उनके सबसे बड़े सिपहसालार थे। सोशल मीडिया पर तो कई बार केजरीवाल के परिवार का हिस्सा बनने की कहानी भी वायरल हो जाया करती थी।

राघव चड्ढा का पंजाब में रुतबा कैसा था कि वहां उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था। उसी दौरान रहते उनकी मुलाकात परिणीति से हुई थी और अब देखिए परिणीति के जरिए वो और फेमस हुए और राजनीति में केजरीवाल नहीं रहे उनके साथ। चर्चा यहां तक रही कि पंजाब कैबिनेट के फैसलों से लेकर ब्यूरोक्रेशी की नियुक्ति तक एक जमाना था जब सब कुछ राघव के फिल्टर से होकर गुजरता था। पंजाब में उनके इसी दबदबे कैश फॉर कैबिनेट जैसे आरोपों ने विरोधियों को हमला करने का

मौका दिया। लेकिन आज हकीकत यह है कि जो राघव कल तक बीजेपी को अनपढ़ों और अपराधियों की पार्टी कहते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य तलाश रहे हैं। राजनीति भी कमाल की चीज है। इस पर एक शेर याद आता है कि 'सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है'।

अब एक पक्ष कह रहा है कि राघव क्या करते? पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही थी। आतिशी को बढ़ा दिया गया था। उनकी सेल्फ रिसपेक्ट को लेकर जगह नहीं बची थी। जो मसले वो उठा रहे थे पार्टी उन्हें समझ नहीं रही थी। इसलिए राघव चड्ढा और उनके मित्र संदीप पाठक ने आंतरिक तानाशाही और पार्टी के आदर्शों के खत्म होने का हवाला देकर पाला बदल लिया। लेकिन दूसरा पक्ष यह पूछता है कि जब पार्टी का मुखिया जेल में था तब तुम लंदन भाग गए थे, आंखों का इलाज करा रहे थे। यह इलाज था या फिर जांच एजेंसिज से बचने का सेफ एग्जिट और बीजेपी में जाना यानि वाशिंग मशीन में धुलना है। विचारधारा का हृदय परिवर्तन है या जरूरत से ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और ईडी, सीबीआई से बचने के चक्कर में तुम यह कदम उठा ले गए। इस सवाल का जवाब जनता पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सियासत में आखिरी फैसला तो जनता करती है। स्वीकार अस्वीकार करना जनता के हित में है। यहां संदीप पाठक का भी जिक्र करना जरूरी है। संदीप पाठक का नाम लोग कम जानते हैं लेकिन संदीप पाठक को आप आम आदमी पार्टी का एक चाणक्य कह सकते हैं। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के एक जमाने में सबसे लाडले थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने बिना शोर शराबे के पंजाब और गुजरात में झाड़ू का झंडा गाड़ा था। यह आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। डाटा के जादूगर हैं। संदीप पाठक को केजरीवाल ने अपना चाणक्य बनाया था। वो संगठन की रग-रग पहचानते थे। एक कैंपेन चला था कि अगर आप चाहते हैं आपके पसंद का मुख्यमंत्री बने तो फोन लगाइए। वो कॉन्सेप्ट इन्हीं का था। आपने तो फोन लगाया पंजाब में, भगवंत मान को चुन लिया। लेकिन उस फोन के जरिए सारा डाटा निकाला गया। किसकी रैली कहां लगवानी है, क्या जुगाड़ करना है। वो डाटा का जो खेल चुनाव में होता है उसकी ये मास्टर माइंड थे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल जब बंद थे तब भी संदीप ही पार्टी को मजबूत कर रहे थे। लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां पर इनको आइसोलेट कर दिया गया था। उस वक्त विजय नायर को बहुत ज्यादा मौका दिया गया था और इनको धीरे-धीरे उपेक्षित कर दिया गया। लेकिन इनके बारे में जानने वाले कहते हैं कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब, गुजरात और गोवा तीनों जगह मजबूत किया था। अब इनको लेकर भी दो लॉजिक आता है। एक लॉजिक है कि संदीप की रणनीतियां लोकसभा चुनाव में फिल हुई थी इसलिए जवाब दे के हटाया गया। दूसरा संदीप का पक्ष है कि केजरीवाल की किचेन कैबिनेट ने उन्हें कलर्क की तरह ट्रीट किया। उनका स्वाभिमान इससे आहत हुआ। एक प्रोफेसर का महव सालों की वफादारी पर शायद भारी पड़ गया और इसीलिए केजरीवाल से ये दूर चले गए। हालांकि संदीप से बीजेपी बहुत कुछ उम्मीद कर रही होगी। क्योंकि जब अपने ही चाणक्य दूसरे के पक्ष में चले जाएं, दूसरे कैंप में जाकर अपने घर की लंका लगाएं तो फिर सवाल तो उठेगा कि लंका में आग लगेगी। क्या विभीषण बताएंगे कि रावण की नाभि में तीर मारना है? मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।

इस कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प किरदार हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल का मामला इस बगावत का सबसे इमोशनल और तीखा मोड़ है। स्वाति मालीवाल वो चेहरा हैं जिन्होंने सालों तक आप की महिला शक्ति को रिप्रजेंट किया। लेकिन 13 मई 2024 को जब स्वाति के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर कथित तौर पर बदसलूकी हुई तो वहां से स्वाति अलग हो गई। एक पक्ष कहता है कि स्वाति के साथ उस आवास के अंदर जो बदसलूकी हुई, उस पर केजरीवाल की खामोशी सत्ता के नशे और तानाशाही का सबसे क्रूर चेहरा है। एक महिला के साथ ऐसा, वो महिला जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। वो महिला जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही, जो दिल्ली की सड़कों पर निकल कर लड़ती थी। दूसरा पक्ष आरोप लगाता है कि व्यक्तिगत चीजों की लड़ाई हुई। जिसके बाद स्वाति मालीवाल महत्वाकांक्षाओं में बीजेपी के लिए खेलने लगी। बीजेपी के पिच से बैटिंग करने लगी। स्वाति ने अब कहा है कि केजरीवाल ने सारे सिद्धांत छोड़ दिए, जिसके बुनियाद पर स्थापना हुई थी। स्वाति का तर्क है कि जिस घर में महिला सांसद सुरक्षित न हो, वहां आम औरत क्या? यहां भी सवाल उस जौहरी पर है जिसने अपने राजनीतिक साख बचाने के लिए अपनी पाटी की पुरानी दोस्त को छोड़ दिया था और अब वह ईंट से ईंट बजा रही हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से बजाया भी था। हालांकि इन सबके बीच में दो छोटी-छोटी कहानी और बड़ी दिलचस्प है। कोठी नंबर पचास और पंजाब का एंगल। दरअसल चंडीगढ़ की कोठी नंबर पचास से कहानी इस बगावत की असली पावर स्ट्रगल और अंदरूनी इजाप को समझाती है। यह कोठी मुख्यमंत्री के नाम पर एलॉट थी, लेकिन यहां पर राघव चड्ढा कब्जा था। वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले। उनके नाम पर जो कोठी एलॉट थी, कहा जाता है उसमें केजरीवाल रहते थे।

अब यह बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री के नाम से कोठी, राघव चड्ढा के नाम की थी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए और अशोक मित्तल के

नाम पर जो थी उसमें केजरीवाल थे। अशोक मित्तल जो है वो बीजेपी में चले गए। अब कोठी-कोठी खेला जाएगा तो मेरी कोठी वापस करो, मैं तुम्हारी कोठी वापस करूंगा। यह अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। हालांकि इनके साथ एक कहानी पंजाब को लेकर भी है। पंजाब में बगावत को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां आप इकलौती सत्ताधारी पार्टी है। पंजाब के छः राज्यसभा सांसदों का एक साथ जाना पार्टी को वहां कमजोर कर रहा है। जनता पूछ रही है जौहरी क्या हो गया? शीश महल बना रहे थे, लेकिन एक ईंट जो है वो खिसक गई और सिर्फ ईंट नहीं खिसकी, ईंट के साथ तिजोरी भी खिसक गई। क्योंकि अशोक मित्तल, विक्रम सहनी और हरभजन सिंह जैसे नामों का जाना बताता है कि राजनीति अब फंड, फेश और फाइलों का खेल बन गई है। यहां एक बहुत दिलचस्प वाक्या है। जिस दिन से यह दल-बदल हुआ उस दिन अरविंद केजरीवाल, अशोक मित्तल के घर में थे। उसी दिन मित्तल ने पाला पलटा और केजरीवाल को घर छोड़ के जाना पड़ा। अब यह भी अपने आप में दिलचस्प कहानी है। हालांकि अशोक मित्तल की कहानी में एक कहानी आती है रेड की। अशोक मित्तल के यहां रेड पड़ी थी। इस वाली कहानी को काफी लोग जोड़ रहे हैं कि 'मोहब्बत से आ जाओ, महत्वाकांक्षा से आ जाओ नहीं तो डरा के भी लाना हम जानते हैं'। लेकिन ठीक है जिसका बिकने का ईमान होता है वो बिक जाता है और जो चला आता है। अब अशोक मित्तल जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं। एक जमाने में उनके पिताजी मिठाई की दुकान चलाते थे। बड़े रईस लोग हैं। समाज में अपने इलाके में इनका रुतबा है। वो शायद राजनीति में विचारधारा से ज्यादा रसूख और सुरक्षा के लिए आए थे और बिजनेशमैन के बारे में एक बात सभी जानते हैं कि बिजनेशमैन डूबती नाव में जाना पसंद नहीं करते। उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर अपने कारोबार को तो कवर फायर कर दिया। इतना जरूर है तो उनका अपना नफा-नुकसान नहीं है। विचारधारा की उनकी लड़ाई थी नहीं। केजरीवाल जी ने टिकट दिया था राज्यसभा का, वो गए थे। अब हो सकता है बीजेपी से पा जाए, नहीं भी पाए तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जिंदाबाद।

हालांकि हरभजन सिंह का जाना क्या एक फेश के जाने जैसा है? कुल मिलाकर सवाल फिर वही जौहरी पर आती है जिसने पार्टी को आंदोलनकारियों के बजाय अपने लड़ाई-झगड़े में उलझा दिया। खैर, कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि यह कोई अचानक से रातो रात हुआ विद्रोह नहीं है। एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। राज्यसभा के इस झटके के बाद अब दिल्ली विधानसभा के विधायकों पर भी दबाव बढ़ने का खतरा है। केजरीवाल के सबसे कमजोर वक्त में यह एक्सट्रा प्रेशर क्या उन्हें तोड़ देगा या केजरीवाल नायक बनकर निकलेंगे? फिलहाल पार्टी के पास तीन राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें बलबीर सिंह सींचेवाल जैसे जमीनी लोग साथ हैं। पार्टी अब पूरी तरह से दिल्ली पंजाब पर फोकस कर रही है। केजरीवाल जिस ऑपरेशन लोटस का आरोप दूसरों पर लगाते थे, आज उनकी अपनी किचेन कैबिनेट के अंदर पूरी तरह सफल हुआ है। पुराने और वफादार साथियों का जाना बताता है कि केजरीवाल के भी तानाशाही रवैये ने पार्टी के अंदर वो माहौल किया जिससे विभीषण पैदा हुए, जिन्होंने लंका जलाई। लेकिन अब सवाल अभी भी वही है कि यह विभीषण वाला काम था, गद्दारी वाला काम था। यह गद्दारी ज्यादा बड़ी है या पहचानने में चूक। क्योंकि जब जौहरी ही हीरे और पत्थरों में फर्क करना भूल जाए तो बगावत खबर नहीं पार्टी तोड़ने का नतीजा बन जाती है। हालांकि पार्टी तोड़ने से ज्यादा जनता का भरोसा तोड़ने का असर है। क्योंकि केजरीवाल उम्मीद लेकर आए थे। अन्ना आंदोलन उम्मीद लेकर आया था। दशकों बाद एक ऐसा आंदोलन आया था, जिससे देश की जनता को उम्मीद हुई थी। हम जैसे कितने मासूम थे जिन्होंने सोचा था कि यह नए दौर के गांधी हैं। लेकिन फिर वही निकला कि सियासत में जो दिखता है उसके पीछे होता है, जो कहा जाता है उसके अलावा कुछ होता है और सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। कब कहां क्या हो पता नहीं। सियासत में सिर्फ एक चीज होता है, वो होता है नफा नुकसान। केजरीवाल को कभी सियासत में आना नहीं था। वो आए, उनके बारे में कहा जाता है तानाशाह बने। केजरीवाल ने जिनको सिखाया उन्होंने केजरीवाल के साथ काण्ड कर दिया। यही सियासत है। इसीलिए शायद हमें लगता है कि सियासत सबके बस की बात नहीं है। सियासत के इस दलदल में, इस कीचड़ में फिलहाल कमल जो है वो थोड़ा और बड़ा होकर खिला है।

बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी

● अमित कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा सांसद बन गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ दिलाई। वही राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा सांसद बन गए हैं। इस बार जब उन्हें जदयू ने उच्च सदन नहीं भेजा तो राष्ट्रपति द्रौपद मुर्मू ने मनोनित कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से प्रकाशित गजट के अनुसार, एक सांसद का कार्यकाल खत्म होने से खाली हुई सीट पर राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है। उनका यह कार्यकाल 2032 तक चलेगा। राज्यसभा सांसद के रूप में हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो गया था। वे आज ही नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं। जदयू ने अप्रैल 2014 में पहली बार उन्हें बिहार से राज्यसभा में भेजा था। वे 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उप सभापति पद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। इससे बाद वे 14 सितंबर 2020 को दूसरी बार राज्यसभा के उप सभापति निर्वाचित हुए।

गौरतलब है कि नीतीश कुमार 16 मार्च को बिहार से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद के एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। विदित हो कि राज्यसभा सदस्य का शपथ लेने के बाद बिहार लौटते ह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पटना स्थित राजभवन (लोकभवन) जाकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा। नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ ही बिहार में उनके लंबे मुख्यमंत्री काल का एक अध्याय समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के पीछे की वजह उनका राष्ट्रीय राजनीति में जाना है। हाल ही में वे बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने पहले ही उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है।संवैध ानिक नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक साथ विधानमंडल और संसद

दोनों का सदस्य नहीं रह सकता, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय लिया। इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने राज्य की जनता और अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। जेडीयू और गठबंधन के भीतर बैठकों का दौर शुरू रहा। राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लग पा रही है। सर्वविदित था कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, जबकि जेडीयू से दो डिप्टी सीएम होंगे। मुख्यमंत्री पद के वर्तमान डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा था और हुआ भी ऐसा ही।

बताते चले कि वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जदयू नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पटना के लोकभवन में एक संक्षिप्त समारोह में राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता है। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राज्य में सम्राट सरकार का दौर शुरू हो गया। बिहार के इतिहास में पहली बार जदयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी राजद नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। उन्होंने भी अपना राजनीतिक करियर राजद से ही शुरू किया था। 2014 में वे राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे। 2018 में वे भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष और फिर राज्य का डिप्टी सीम बनाया। ओबीसी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कोइरी समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए का दामन छोड़ा था, तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था। उस वक्त सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने तक सिर पर मुरेठा (पगड़ी) बांधे रखने का संकल्प लिया था। सम्राट चौधरी दो बार परबत्ता से विधायक रहे, दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे और दो बार के डिप्टी सीएम। 2024 में डिप्टी सीएम के साथ-साथ वित्त मंत्री बनाए गए। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं और एक बार फिर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थीं। इसके बाद से ही राज्य में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरो पर थी। बहरहाल नीतीश की राज्यसभा सांसद के रूप में केंद्र की राजनीति में एंट्री ने सम्राट के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया।

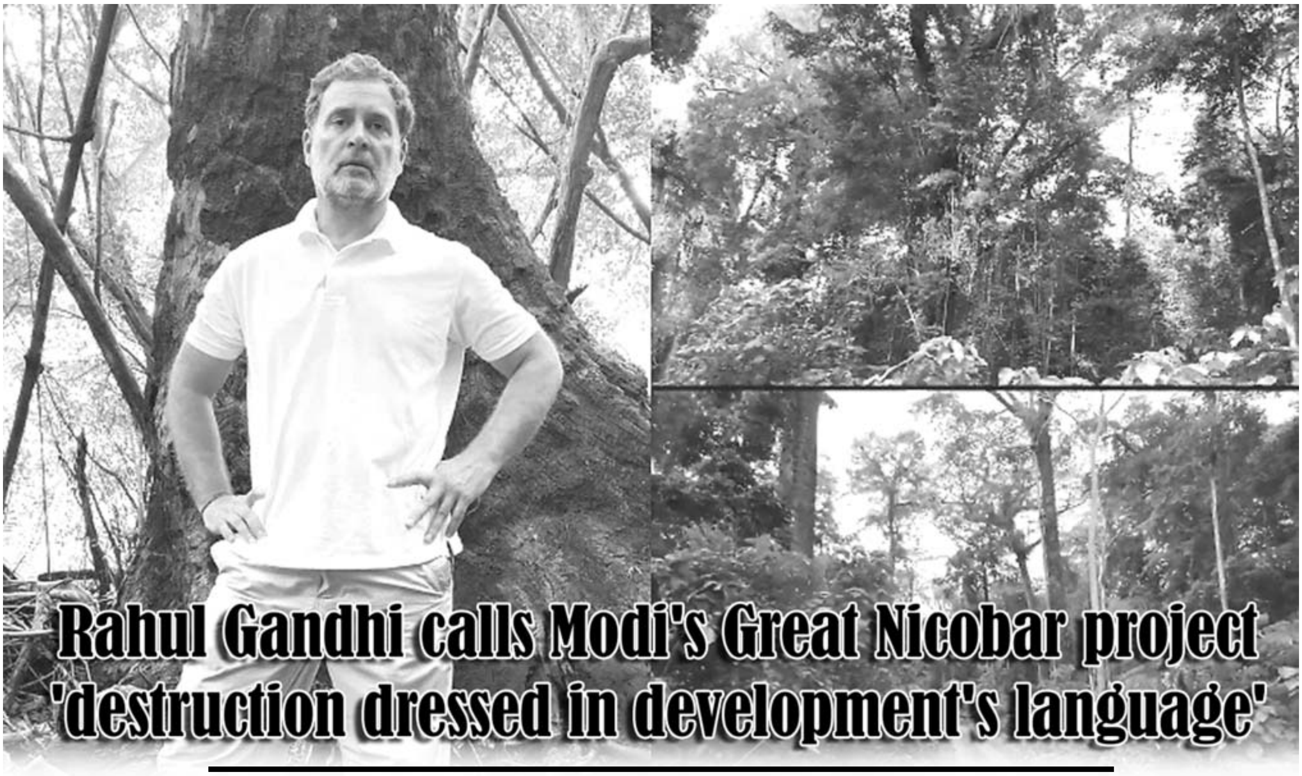

Rahul Gandhi calls Modi's Great Nicobar project 'destruction dressed in development's language'

Indian opposition leader Rahul Gandhi on Wednesday criticized a proposed $9 billion (•7.69 billion) port-and-city project on Great Nicobar Island that the government is pushing as of "strategic, defense and national importance."

"What is being done in Great Nicobar is one of the biggest scams and gravest crimes against this country's natural and tribal heritage in our lifetime," Gandhi said in a video message posted on X. Gandhi called it "destruction dressed in development's language" in the video showing him walking through the island's forests.

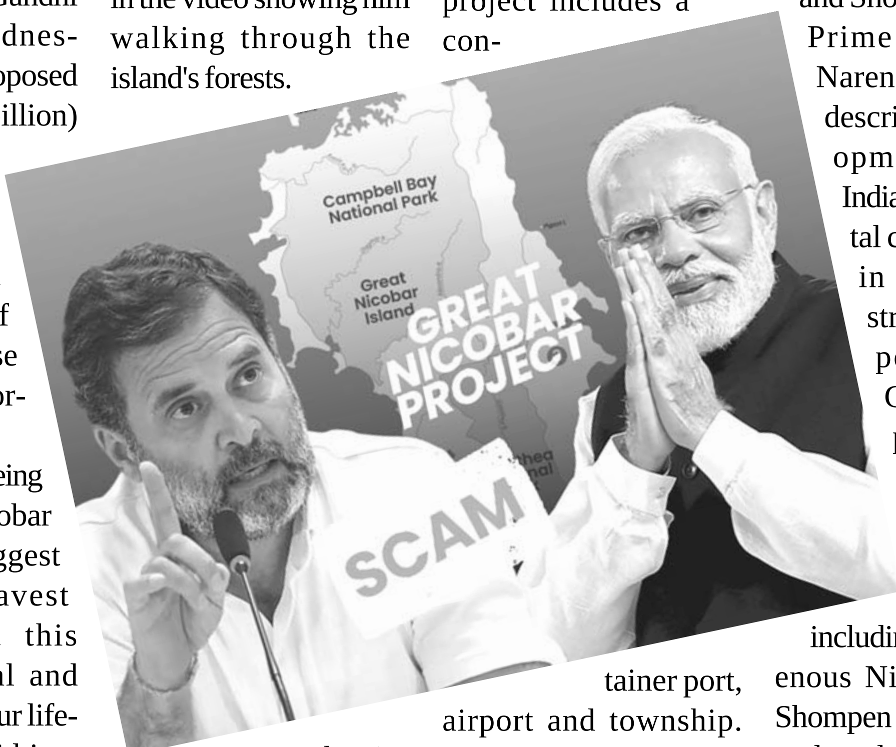

The island lies near the entrance to the Strait of Malacca, one of the world's busiest shipping lanes, and the project includes a container port, airport and township. Critics say it would destroy large areas of rainforest and threaten Indigenous communities, including the Nicobarese and Shompen peoples.

Prime Minister Narendra Modi has described the development, which India's environmental court approved in February, as strategically important, But Gandhi said the plan "must be stopped."

About 9,000 people live on the island, including 1,200 Indigenous Nicobarese and Shompen people, the latter largely avoiding outside contact, according to Survival International.

विपक्ष ने रोक दी नारी शक्ति की उड़ान

● अमित कुमार

महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल 54 वोट से गिर गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल पास नहीं हुआ, सदन में वोटिंग के दौरान इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। संविधान (131वां संशोधन) संशोधन बिल के लिए लोकसभा में कुल 489 वोट पड़े। बिल के पक्ष में 278 वोट, जबकि बिल के खिलाफ 211 वोट पड़े। किरण रीजिजू ने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाकर रहेंगे। लोकसभा में इस चर्चा हुई। चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार-बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहाँ नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को 'महिलाओं का आक्रोश' न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, 'मैं नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था, यह भाषा सदन की मर्यादा के विपरीत है... अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है... यह नेता प्रतिपक्ष का किस तरह का बर्ताव है, क्या भाषा है? क्या उन्हें लगता है कि देश उनकी यह भाषा नहीं सुन रहा? वे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं... वे सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं... सदन में बोलने की कला आपके यहां बहुत वरिष्ठ लोग हैं उनसे सीखें, या प्रियंका गांधी से सीख लें।' गृह मंत्री ने कहा कि ये कहते हैं कि यह क्रूर बिल है। महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है। ये उत्तर बनाम दक्षिण करते हैं। कल इतना समझाने के बाद भी अगर यह बयान आ रहा

है, तो यह जानबूझकर दिया गया बयान है। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है, हमने धारा 370 समाप्त की, उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर बनाया, विरोध किया, CAA लाए, विरोध किया, तीन तलाक समाप्त किया, विरोध किया, GST लाए, विरोध किया, आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया, नया संसद भवन बनाया, विरोध किया, CDS बनाया, विरोध किया, नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया, एयरस्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। इन्होंने अच्छा-बुरा सोचे बिना नरेन्द्र मोदी जी जो कर रहे हैं, उसका विरोध करने का ठान लिया है। महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उन्हें संबल बनाने के लिए, उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए, विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए... जिसके विरोध का भी सामना करना पड़े, हम करेंगे, हम लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अच्छा-बुरा सोचे बगैर इन्होंने नरेंद्र मोदीजी जो कर रहे हैं, उसका विरोध करने की ठान लिए हैं। मैंने तो सोचा था कि आज महिलाओं को आरक्षण के लिए बिल आ रहा है, इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने इसका भी विरोध किया। ये जो बिल अर्जुन राम मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 850 तक करने की बात है। अनुच्छेद 81(3) में नवीन जनसंख्या के अनुसार परिभाषित करने के प्रावधान को समाप्त करते हैं। उन्होंने संशोधन भी गिनाए और कहा कि सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि माताओं-बहनों को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। 2023 में सर्वसम्मति से यह बिल पारित हुआ, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। यह बिल मोदीजी ला रहे हैं, बिल पारित होता है तो माताओं के बीच मोदीजी का यश बढ़ेगा। मोदीजी ने बड़ा एडवर्टाइज

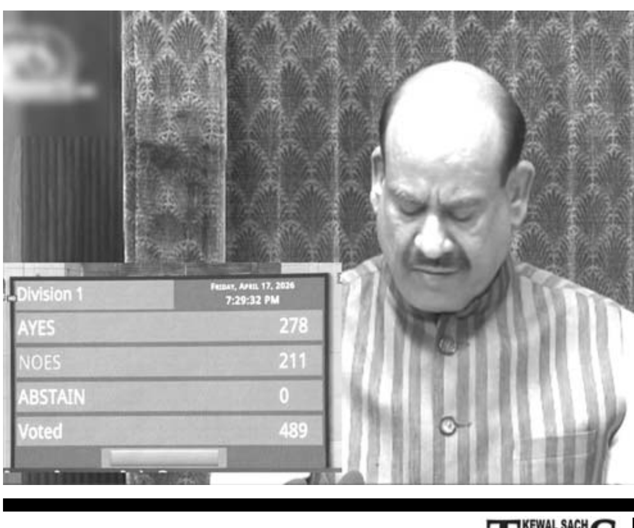

देकर यश देने का भी कह दिया। इस सदन ने 2023 में जो 33 फीसदी आरक्षण का सदन ने फैसला किया था, उससे ये पीछे हट रहे हैं। हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए। ये नारा मोदी जी का नारा, इंदिराजी का है। यहां आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहां से लाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने

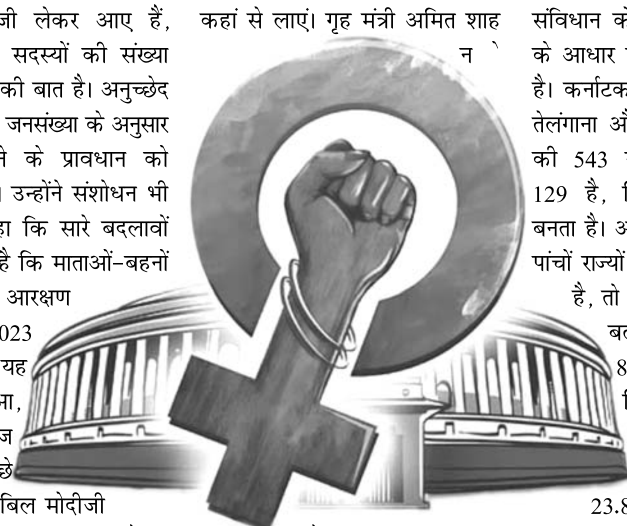

कहा कि मैं कांग्रेस से कहता हूं कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बिना सत्ता नहीं मिलेगी, यह समझ आ गया, तब आज ओबीसी की माला जप रहे हो। यह दिखावटी प्रेम है, इस देश का पिछड़ा वर्ग भी जानता है और देश की पूरी जनता भी जानती है और आज से देश की महिलाएं भी जानेंगी कि उनका अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना।

यहां कुछ सदस्यों ने भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं यहां संविधान की नीतियों को स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। इंडी अलायंस वाले तुष्टिकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम आरक्षण की मांग खड़ी करना चाहते हैं और ये संविधान की बात करते हैं। कोई मुझे बता दे कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और केरल इन पांच राज्यों की 543 सीटों में वर्तमान संख्या 129 है, जिसका प्रतिशत 23.76 बनता है। अब वृद्धि के बाद जब इन पांचों राज्यों का आवंटन किया जाता है, तो सीटों की संख्या 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी। 816 में इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 23.87 आएगा। पहले 23.76 प्रतिशत था और अब 23.87 होगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी जाति जनगणना का विरोध किया। मोदी सरकार में ओबीसी आयोग को मान्यता मिली। बीजेपी को धर्म के आधार पर आरक्षण नामंजूर। कांग्रेस ने 1980 में मंडल आयोग के सुझाव नहीं माने। मोदी सरकार में 40 प्रतिशत मंत्री ओबीसी हैं। चुनाव में महिलाएं इनसे हिसाब मांगेगी। गृह मंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर कहा एक घंटे का समय दीजिए संशोधन कर देंगे। विपक्ष समर्थन दे तो 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का संशोधन लाएंगे। जब से यह बिल आया है, तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू किया है कि

जाति जनगणना को टालने के लिए सरकार संविधान संशोधन लेकर आई है। मैं बताना चाहता हूं कि तीन माह पहले ही हम जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है। जाति जनगणना शुरू हो चुकी है, उसका पहला चरण चल रहा है। हम जब शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं, वे उत्तर-दक्षिण का भेद कराना चाह रहे हैं। यह हम नहीं होने देंगे। दक्षिण के साथ अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा थय लगा कि दक्षिण बनाम उत्तर का नैरेटिव नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दक्षिण के राज्यों का इस सदन पर उतना ही अधिकार है, जितना उत्तर के राज्यों का है।

1976 में इस देश की आबादी 56.79 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। 56.79 करोड़ की आबादी में जितने सांसद थे, उतने ही 140 करोड़ की आबादी में भी रखना, ये इनका (विपक्ष) मानना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया और फिर इसे फ्रीज कर दिया गया। 1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी गई। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने कानून लाकर परिसीमन पर रोक लगाई, लेकिन आज ये कितने शक्तिशाली हैं कि विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाह रहे हैं। उस वक्त भी कांग्रेस ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित कर रही है। कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त कीं कि परिसीमन अभी क्यों लाया जाए? तो मैं बता दूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अब ये कहते हैं कि बिल लाते समय ऐसा जिक्र क्यों किया गया? यह हमने नहीं किया। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब वे इसे फ्रीज करके गई थी, वह फ्रीज की गई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन होता है इसलिए हम इसे लेकर आए। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी 127 सीटें हैं, जहां निर्वाचन क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यह 'एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य' के सिद्धांत की मूल भावना के विपरीत है। कुछ जगहों पर 45 लाख मतदाताओं का एक प्रतिनिधि होता है, तो कुछ जगहों पर 6 लाख मतदाताओं का एक प्रतिनिधि। इसका नतीजा यह होता है कि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हर वोट का मूल्य बराबर नहीं होता। गृह मंत्री शाह ने कहा कि हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन से ही SC और ST जिसकी संख्या बढ़ती है, उसकी सीटें बढ़ने का भी प्रावधान है। एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वह SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का भी विरोध कर रहे हैं।

इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सभी ने कहा है कि यह संविधान संशोधन जो आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। पहला, महिला सशक्तिकरण करने वाले संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। दूसरा कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य. .. यह सिद्धांत जो हमारे संविधान के मूल में है, जिसे संविधान सभा ने तय किया था, उस संविधान की स्पिरिट को लागू किया जाए।

बहरहाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी। यह बात परिसीमन से जुड़ी हुई थी। मोदी सरकार को परिसीमन इस आधार पर करना था, जिसमें उसे जातिगत जनगणना के आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं होती और

मनमानी करने की पूरी आजादी होती। ऐसे में मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष मोदी सरकार का साथ दे। पूरे देश ने देख लिया है कि जब विपक्ष एकजुट होता है तो कैसे मोदी सरकार को हराया जाता है। वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। 2023 में पास बिल को लागू करें सरकार। यह महिला आरक्षण की नहीं परिसीमन की बात थी। परिसीमन पर विपक्ष का साथ देना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए। उन्होंने कहा कि कल संसद में विपक्ष की बड़ी जीत हुई। प्रियंका ने कहा कि भाजपा का महिलाओं के संदर्भ में एक इतिहास है। ये इतिहास बहुत स्पष्ट है। सिर्फ सदन में विपरीत कहने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की महिलाओं ने उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, महिला खिलाड़ियों को देखा, मणिपुर की महिलाओं को देखा। मोदी सरकार ने कभी उनकी सुध नहीं ली और आज संसद में 'महिलाओं का मसीहा' बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने अपने-अपने भाषणों में कहा कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर सहमत नहीं होगा तो न कभी चुनाव जीत पाएगा, न ही सत्ता में आ पाएगा। इन बातों से ही साफ हो गया कि सरकार की मंशा क्या थी। मेरा मानना है कि सरकार द्वारा जो साजिश रची गई, उसका उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। इसके लिए सरकार ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार चाहती थी कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष यह बिल पारित करवा दे। ताकि उन्हें मनमाने तरीके से परिसीमन की आजादी मिल जाए, जिससे मोदी सरकार को जातिगत जनगणना का सहारा न लेना पड़े। मोदी सरकार का मानना था कि अगर बिल पारित होगा तो उनकी जीत होगी और बिल पारित नहीं हुआ तो विपक्ष को महिला विरोधी बता देंगे। भाजपा ऐसा कर खुद को महिलाओं का मसीहा साबित करना चाहती थी।

गौरतलब है कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में अपनी चुनावी मुहिम तेज करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, कल आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद में क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने देश से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि वे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस बिल के पीछे एक शैतानी विचार छिपा था। वे भारत का चुनावी नक्शा

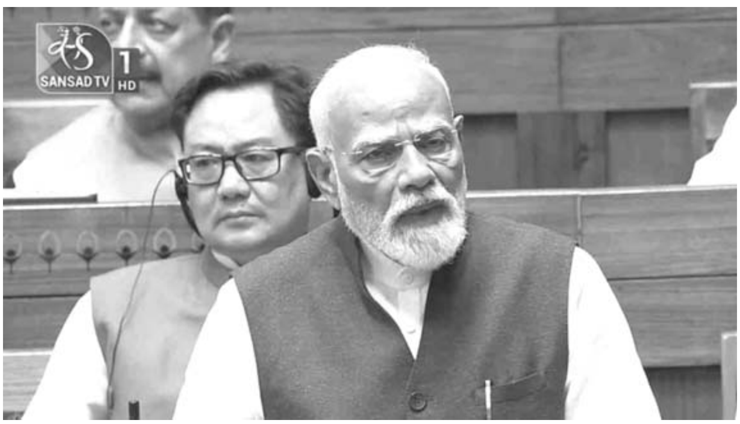

बदलने की कोशिश कर रहे थे। वे हर राज्य को मिलने वाली सीटों की संख्या बदलना चाहते थे। वे दक्षिण भारतीय राज्यों, नॉर्थ-ईस्ट राज्यों और दूसरे छोटे राज्यों को कमजोर करना चाहते थे। प्रधानमंत्री हमारे संविधान पर हमला कर रहे हैं।राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह महिला आरक्षण के नाम पर अपने गलत इरादों को देश पर थोपना चाहती थी, जिसे विपक्ष ने रोक दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार 16 अप्रैल को एक नया विधेयक लेकर आई और दावा किया कि वह महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की कोशिश कर रही है, जबकि यह विधेयक पहले ही 2023 में पारित हो चुका है। इसी वजह से विपक्ष ने उनका साथ नहीं दिया और महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक गिर गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि जिस बिल को महिला आरक्षण के नाम पर पेश किया गया, उसका असली मकसद परिसीमन के जरिए तमिलनाडु की लोकसभा सीटों को कम करना था। आगामी चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन की ओर से केंद्र के केंद्रीकरण के प्रयासों का विरोध करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से तमिलनाडु को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं होने देंगे। राज्य अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा।

विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने लोगों के बीच अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने विपक्ष को साफ-साफ कह दिया था कि वे बिल का क्रेडिट ले सकते हैं। मैं तो बस आम परिवारों की बहनों को संसद और विधानसभाओं में लाना चाहता था, लेकिन यह नेक प्रयास विफल हो गया। 21वीं सदी की नारी देश की हर राजनीतिक घटना पर पैनी नजर रख रही है। वह इन दलों की मंशा को भांप चुकी है और सच्चाई भी जानती हैं। महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने जो पाप किया है, उसकी सजा उन्हें जनता जरूर देगी। भारत का हर नागरिक आज देख रहा है कि कैसे नारी शक्ति की उड़ान को रोकने की साजिश रची गई है। हमारे भरसक प्रयासों के बाद भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। मैं इसके लिए देश की सभी माताओं और बहनों से हृदय से क्षमाप्रार्थी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वह आज देश की बेटियों और बहनों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आए हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और कुछ दलों ने देश हित से ऊपर अपना स्वार्थ रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति ने विपक्ष का रवैया देखा है। उन्होंने दुख जताया कि बिल गिरने पर विपक्ष मेज थपथपा रहा था। उन्होंने इसे महिलाओं के हितों के खिलाफ कदम बताया और कहा कि देश इसे याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बिल किसी से कुछ लेने का नहीं, बल्कि सभी को अधिकार देने का था और 40 साल से लंबित महिलाओं के हक को लागू करना था। उन्होंने माता और बहनों से क्षमा मांगी। मोदी ने कहा कि विपक्ष बिल गिरने पर ताली बजाकर जश्न मना रहा था, जो नारी आत्मसम्मान पर चोट है। उन्होंने इसे ईमानदार प्रयास की भ्रूण हत्या बताया और कहा कि विपक्ष को अपने इस कदम की सजा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था। प्रधानमंत्री ने कहा, नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन सभी राज्यों की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। सब राज्यों की समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी, लेकिन इस प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है।

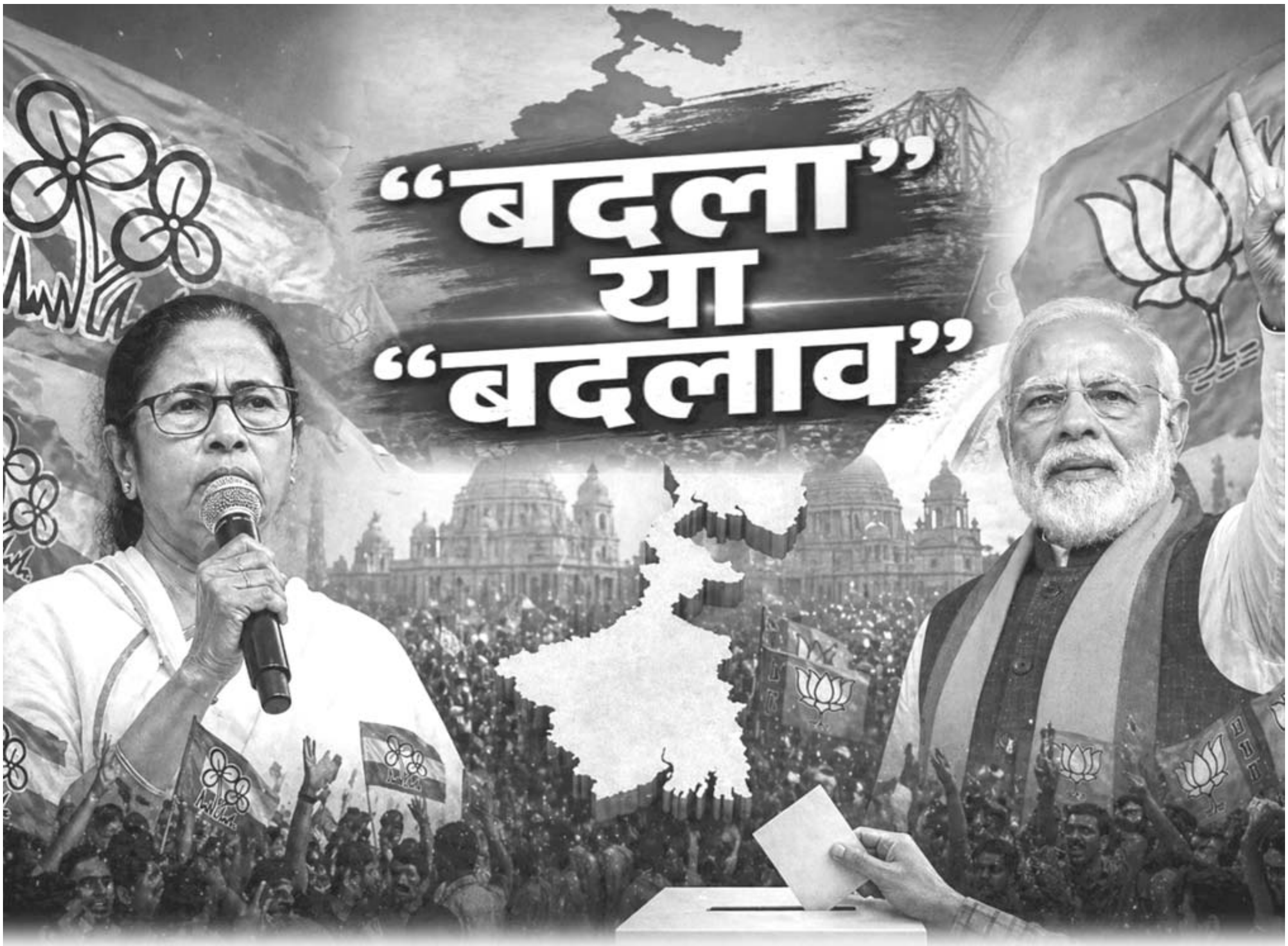

● अजित दूबे

क्या 2026 की ये एग्जिट पोल वाकई में पश्चिम बंगाल की नब्ज को पढ़ रहे हैं या फिर टीवी की स्क्रीन पर चमकता हुआ ऐसा कागजी शोर है जो शायद चार मई को नतीजों के साथ ढ़ह जाएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन नोएडा की टीवी स्टूडियो में आंकड़ों का तूफान खड़ा है। हर चैनल अपनी जीत की एक अलग कहानी सुना रहा है। कई टीवी चैनलों ने ममता बनर्जी की वापसी को तय बता दिया है तो बहुत सारे टीवी चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि इस बार ममता के साथ खेला हो गया और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिल जाएगा। लेकिन एक सच यह भी है कि 2021 में इन्हीं तमाम टीवी चैनलों के सर्वे आईना देख चुके थे, जब लगभग सारे सर्वे गलत हुए थे। इस बार भी तस्वीर को लेकर बहुतेरे सवाल हैं। दावे बड़े हैं, आंकड़े उलझे हैं, सच जो है पर्दे के पीछे है और जनता के मन में सिर्फ यह सवाल नहीं है कि बंगाल जीतेगा कौन? सवाल यह भी है कि एग्जिट पोल पर क्या भरोसा करना चाहिए या फिर उसमें भी कोई एजेंडा नरेटिव होता है। क्योंकि बंगाल के चुनाव डाटा से कम दिल से ज्यादा होते हैं। बंगाल की अस्मिता, गुस्सा, भरोसा, चुप्पी लिखकर कई बार फैसला करते हैं जो शायद ग्राफ नहीं पकड़ पाता और इस बार बंगाल का चुनाव ऐसा ही था। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। सुरक्षा को लेकर बहुत तेरे सवाल खड़े थे। बेरोजगारी को लेकर नाराजगी के लहर थी। दूसरी तरफ ममता की कई योजनाएं और उनका मां, माटी, मानुष के चलते जमीन जुड़ाव की पकड़ इन सबके बीच खड़ा था। और इन सारी चीजों के बीच में वो महिला वोटर, वो प्रवासी मजदूर, वो साइलेंट वोटर जो आखिरी में खेल पलट सकता है, उसका रुझान किधर रहा, वो सब कुछ तय करता है।

गौरतलब है कि अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की राजनीति कितनी कमजोर हो सकती है। अगर दीदी जीत जाती हैं तो राहुल गांधी के सामने वो कैसे एक नई मुसीबत पैदा कर सकती हैं। बीजेपी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर चुनाव क्या केवल एक चुनावी जीत है या फिर वैचारिक जीत का अंतिम मोर्चा है? संदेशखाली में मंत्रियों के पास मिली नोटों की गड्डियां, सुरक्षा को लेकर सवाल, इनका क्या असर रहा? क्या महिला वोटर ने सुरक्षा के नाम पर वोट दिया या फिर जो ममता दीदी ने स्कीम निकाली है पैसा देने की उसके नाम पर गया? क्या सीएए और बंगाली अस्मिता जैसे मुद्दों ने वाकई बंगाल में वोटर को दो मुद्दों में बांटा है। बहुत सारे एंगल हैं और आज तमाम एंगल को लेकर इमोशनल और राजनीतिक खेल की गहराई को समझते हैं।

बताते चले कि एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। 4 मई को नतीजे निकल कर आएंगे। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए एग्जिट पोल जो आए वो किसी सस्पेंस फिल्म जैसे हैं। जहां पर कुछ एजेंसियों ने पहली बार बीजेपी को ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ता दिखाया। कुछ ऐसी हैं जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के वर्चस्व पर भरोसा कर रही हैं। अब अगर अलग-अलग डीकोड करते हैं तो मैट्रिक्स ने बीजेपी को 141 से 146 सीटें दिखाई हैं। टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं। चाणक्या ने बीजेपी को 150 से 160 सीट दे दी है। टीएमसी को 130 से 140 यानी उनके हिसाब से

सरकार जो है वो बीजेपी की आ रही है। दावों का सबसे आक्रामक दौर जो है वो प्रजा पोल के साथ शुरू हुआ है। उन्होंने बीजेपी की सीटों को 178 से 208 तक दे दिया। यानी अबकी बार बीजेपी बंगाल में 200 पार। वहीं पीमार्क ने बीजेपी को 150 से 175 और टीएमसी को 118 से 138 में रखा है। पोल डायरी के आंकड़े जो हैं वो भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। 142 से 171 और टीएमसी के लिए 99 से 127 तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी एजेंसियां जो है वो बीजेपी की ही सरकार बना रही हैं। कई दूसरी एजेंसियां भी हैं जो ममता बनर्जी पर भरोसा जता रही हैं। जैसे पिपुल प्लस ने टीएमसी को 171 से 187 सीटें दी हैं। यानी प्रचंड बहुमत उनकी आने वाली है। बीजेपी उनके हिसाब से 95 से 110 सीटें पर जाएगी। जनमत पोल्स ने तो 200 पार करा दिया है। 195 से 205 सीटें ममता बनर्जी को दी है और बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी है। कुल मिलाकर आप सारे पोल्स का एवरेज निकालें, जिसे हम पोल ऑफ पोल्स कहते हैं और देसी भाषा में कहते हैं कि पोल के पापा। सारा मिलाकर तो सारे एग्जिट पोल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो उसके हिसाब से बीजेपी 145 सीटें और टीएमसी 142 सीटों पर खड़ी है। इस हिसाब से बंगाल के लिए बहुमत में जो 148 चाहिए वो कोई नहीं पा रहा। हो सकता है त्रिकोणीय कहानी जो है वो भी बन जाए। सात सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाएंगी और हो सकता है कि वो किंग मेकर हो जाए। लेकिन ये खयाली पुलाव वाली बातें हैं। आमतौर पर पोल ऑफ पोल्स का एवरेज नहीं होता। वो सिर्फ एक डायरेक्शन लेने के लिए होता है कि ज्यादातर पोल्स में कौन ज्यादा आगे चल रहा है, तो उसके हिसाब से फिलहाल बीजेपी दिख रही है। लेकिन इस पर क्या भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आप एक्जिट पोल पर भरोसा करने की बात करते हैं, आपको 2021 याद आता है।

पश्चिम बंगाल में एक्जिट पोल की सबसे बड़ी कमजोरी उनका पुराना रिकॉर्ड है। 2021 के चुनाव में लगभग हर बड़ी एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई थी। उस समय एक्सिस माय इंडिया और एवीपीसी वोटर जैसे दिग्गजों ने बीजेपी को बहुमत के करीब बताया था। शायद उस बार का सबक ऐसा रहा कि एक्सिस माय इंडिया ने तो इस बार एनाउंसमेंट कर दी कि पश्चिम बंगाल के एक्जिट पोल वो डालेंगे ही नहीं। पिछली बार भी बीजेपी को 185 सीटें दी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल कहानी उल्टी थी। टीएमसी 215 पाई थी और बीजेपी केवल 77 सीटों पर रह गई थी। उस वक्त दीदी की अंदरूनी लहर को पकड़ने में सारे एक्जिट पोल फेल थे। 2021 का सबसे बड़ा सबक यह था कि बंगाल का वोटर सर्वे करने वालों को अपनी पहली पसंद कभी नहीं बता रहा था और इस बार तो बंपर वोटिंग हुई है। 90 प्लस से अधिक जो पिछले कई दशकों के मुकाबले ज्यादा है। अब इतना भारी मतदान जो हुआ है वो किसी गहरी भावना इमोशनल वोटिंग का संकेत कई बार माना जाता है और इसीलिए शायद क्या सारी एजेंसीज उस इमोशन को समझ पाएंगी। वैसे 2026 का चुनाव न केवल सत्ता का फैसला करेंगे बल्कि सर्वे एजेंसीज की साख की भी परीक्षा करेंगे और यह भी तय करेंगे कि महिलाओं को क्या चाहिए? मुफ्त की योजनाएं चाहिए या सुरक्षा चाहिए? क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल महिला वोटर्स का माना जा रहा है।

गौरतलब है कि बंगाल की आधी आबादी की लड़ाई दो अलग-अलग छोड़ के बीच में है। एक तरफ संदेशखाली का मुद्दा है, जहां महिलाओं के मन में सुरक्षा और सम्मान को लेकर गुस्सा है। कई सर्वे इसी आक्रोश को आधार बनाकर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। संदेशखाली की घटनाओं ने ममता सरकार की महिला हितैषी छवि पर चोट पहुंचाई है और बीजेपी इसे यूटिलाइज करना चाह रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो योजनाएं चलाईं; जिसमें लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ साथी। उनका यह मानना है कि ग्रामीण बंगाल की महिलाओं के लिए केवल सरकारी योजनाएं ही नहीं

उनके वजूद और आर्थिक सम्मान की गारंटी हैं। लक्ष्मी भंडार से मिलने वाली महीने की मदद ने महिलाओं को बड़ा सहारा दिया है। 2021 में भी महिलाओं ने टीएमसी को जीत दिलाई थी। अब सवाल यह है कि संदेशखाली का गुस्सा बड़ा है या योजनाओं से जो लाभ मिलेगा वो महिलाओं का मन बदलेगा। क्या बंगाल की महिला सुरक्षा के सवाल पर वोट दिया है या फिर आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देगी? यही सारा खेल होने वाला है। हालांकि इस डिवेट में एक सवाल बार-बार यह भी उठ रहा है कि क्या मुफ्त की योजनाएं जो दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए अमृत साबित हुई, वो ममता बनर्जी के लिए भी अमृत साबित होंगी? या फिर भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों घर से मिले नोट ने ऐसा गुस्सा पैदा किया है जिसका असर शायद इन योजनाओं पर भारी पड़ जाए। यह अपने आप में एक देखने वाली बात है कि लक्ष्मी भंडार की जो आर्थिक मदद है, जो लगभग हर राज्य में चली है, वो क्या इस राज्य में ममता को भी राहत देगी? यह बड़ी बात है। लेकिन एक बात और है कि बंगाल के चुनावों का असर देश-दुनिया पर होने वाला है।

बंगाल के नतीजों का असर सिर्फ कोलकाता तक नहीं होगा बल्कि वो दिल्ली की राजनीति की दशा-दिशा भी तय करेगा। अगर ममता बनर्जी यहां सत्ता में चौथी बार वापसी करती हैं तो यह केवल एक राज्य की जीत नहीं होगी बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल होगा। ममता बनर्जी इसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आएंगी। वो विपक्षी गठबंधन की सबसे प्रभावी, अनुभवी और मजबूत चेहरा बनेंगे जो सीधे तौर पर विपक्ष के नेतृत्व के लिए राहुल गांधी के दावे को चुनौती देंगे। अगर ममता हार जाती हैं तो इससे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का एक और बड़ा स्तंभ गिर जाएगा और बीजेपी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दौर से ही बंगाल में अपनी सरकार का ख्वाब देख रही है वो वैचारिक तौर पर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर जाएगा। बीजेपी के लिए बंगाल एक अंतिम मोर्चा की तरह है। यह किला जीतने के बाद वो अपने आप को अजेय मान लेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान जीत लिया। अब कोई ऐसा किला नहीं जो बड़े पैमाने पर बचा हो। साउथ में है कुछ चीजें लेकिन वो अपने आप को मान लेंगे कि हम अजेय हो गए। यहां की जीत का मतलब केवल 294 सीटों को गणित नहीं है, विजय का शिखर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिलाना भारत के लिए उत्तर, पश्चिम, पूर्व भारत को पूरी तरह फतेह करने जैसा होगा और इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत इसमें झोकी है। क्योंकि वो जानती है कि यहां की जीत उन्हें ऐसी राजनैतिक ताकत देगी, जिसे तोड़ना मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने चुनाव के आखिरी समय में टीएमसी पर सीधा निशाना साधा था। अब कई राजनैतिक जानकार उसे लांग टर्म स्ट्रेटजी मान रहे थे। कांग्रेस शायद चाहती है कि बंगाल में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव खत्म हो। बंगाल में मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के बीच में हो। चूंकि बीजेपी के पास ममता के कद का कोई इतना बड़ा नेता नहीं है, इसलिए उन्होंने ममता बनाम मोदी का मुकाबला बनाया ताकि नेशनल नेरेटिव को जिंदा रखा जाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि किसके मुद्दे भारी पड़ेंगे। भ्रष्टाचार वाले मुद्दे, सुरक्षा वाले मुद्दे या बंगाली अस्मिता वाले मुद्दे। क्योंकि बीजेपी ने पूरा चुनाव भ्रष्टाचार, सुरक्षा, घुसपैठ जैसे ज्वलंत मुद्दों पर रखा। भर्ती घोटाले की जांच, मंत्रियों घर से बरामद नोटों के ढ़ेर, मध्यम वर्ग के मन में टीएमसी के प्रति गहरी नाराजगी का सवाल पैदा की।

गौरतलब हो कि ममता का मतदाता जो है वो भ्रष्टाचार को नापसंद तो करता है लेकिन ममता भी उसके मन में डाल रही हैं कि यह बाहरी लोग हैं, बाहरी हस्तक्षेप है, दिल्ली के फरमान हैं। मैं तुम्हारी अपनी हूं। ममता बनर्जी इस नब्ज को दुनिया में सबसे बेहतर पहचानती हैं। उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी बंगाल के चुनाव को बंगाल की बेटी अमतेने बाहरी ताकत का युद्ध बनाया।

बंगाली अस्मिता, भाषा, सांस्कृतिक गौरव अक्सर किसी भी घोटाले या प्रशासनिक चूक से ऊपर चलाता है। हालांकि ममता तीन बार जीत चुकी हैं। इस बार क्या इंकबेसी भी होगी? सीएए के मुद्दे पर जहां बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की, वहीं ममता ने इसे बंगाली पहचान पर हमले के रूप में पेश किया। दीदी ने बड़ी चतुराई से दिल्ली के नेताओं के दौरों को बंगाल की संस्कृति और परंपराओं पर हमले की तरह प्रस्तुत किया। जिसके चलते मनोज तिवारी और कई नेताओं को मच्छी खाना पड़ा। अब देखना यह है कि तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद जब कुछ सर्वे टीएमसी को भी 200 प्लस सीट दे रहे हैं तो क्या इस बार भ्रष्टाचार का कड़वा सच अस्मिता के मीठे एहसास को निगल जाएगा या बंगाली गौरव एक बार फिर भ्रष्टाचार के दाग को धो देगा। हालांकि झोल जो है वो एग्जिट पोल में तो है ही। एग्जिट पोल में अक्सर देखा गया है कि सैंपलिंग संकुचित तरीका है। शहरों के बड़े और विकसित इलाकों में खड़े होकर सैंपल लिए आते हैं। अब वो सुंदरबन के सुदूर गांव, चाय बागान, जंगल महल की तंग गलियों वहां तक जाते नहीं है। बंगाल में एक साइलेंट वोटर की संस्कृति भी है, जहां लोग डर या स्थानीय राजनीतिक दबाव के चलते अजनबियों को अपनी असली पसंद बताने से कतराते हैं। इसका नतीजा भी यह होता है कि एजेंसियों के पास केवल बाहर बाहर का डाटा होता है, अंदर दिल का डाटा नहीं होता है और कई बार इसका बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे पिछली बार हुआ था।

विदित हो कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक पहचान, क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय के टकराव का भी इम्तिहान होगा। अगर 2026 में ममता बनर्जी हारती हैं, तो यह सिर्फ एक मुख्यमंत्री की हार नहीं होगी। यह बंगाल की राजनीतिक दिशा बदलने वाला क्षण हो सकता है। पश्चिम बंगाल में

चुनाव कभी सिर्फ सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं रहे। यहां सत्ता परिवर्तन अक्सर एक बड़े राजनीतिक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का संकेत देता है। 2011 में 34 साल पुराने वामपंथी शासन का अंत हुआ था। उस समय ममता बनर्जी का उभार "परिवर्तन" के रूप में देखा गया। एक ऐसा बदलाव जिसने राज्य की राजनीति को वर्ग-आधारित विमर्श से निकालकर क्षेत्रीय पहचान और वेलफेयर पॉलिटिक्स की ओर मोड़ दिया। अब, 2026 के चुनावों को लेकर जो सवाल उभर रहा है, वह सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा बल्कि यह है कि अगर ममता बनर्जी हारती हैं, तो क्या यह भाजपा के लिए "बदला" होगा या बंगाल के लिए एक नया "बदलाव"? बंगाल का राजनीतिक इतिहास अचानक झटकों से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बनते सामाजिक समीकरणों से तय होता है। 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटों के साथ अपनी पकड़ मजबूत की थी। लेकिन अगले पांच साल में एक बड़ा बदलाव चुपचाप तैयार हो रहा था। भाजपा, जो कभी राज्य में हाशिए की ताकत थी, उसने अपना वोट शेयर लगभग 10% से बढ़ाकर 2021 तक करीब 38% कर लिया। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। यह दिखाता है कि उसका कोर वोट बैंक अभी भी मजबूत है। यानी, बंगाल में राजनीतिक बदलाव "एक लहर" से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे शिफ्टिंग ग्राउंड से आता है। आज बंगाल की राजनीति लगभग पूरी तरह दो ध्रुवों में सिमट चुकी है-तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। वामपंथ और कांग्रेस, जो कभी सत्ता के केंद्र में थे, अब राजनीतिक हाशिए पर हैं। इससे चुनाव का चरित्र भी बदल गया है। अब यह बहुकोणीय नहीं, बल्कि सीधा टकराव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगभग 40% वोट हासिल किए और 2021 विधानसभा चुनाव में भी वह करीब 38% पर बनी रही। यह संकेत है कि भाजपा का समर्थन अस्थायी नहीं, बल्कि स्थिर और संरचनात्मक होता जा रहा है, बीजेपी का सिर्फ वोट शेयर का मामला नहीं, बल्कि बंगाल में 'पोलटिकल वैक्कयूम' भरने की कहानी है, जो वामपंथ के पतन के बाद बना। लेकिन दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर भी 43-48% के बीच स्थिर रहा है, जो बताता है कि उसकी जड़ें अभी भी गहरी हैं।

लब्बोलुआब है कि भाजपा के लिए बंगाल सिर्फ एक और राज्य नहीं है, यह एक प्रतीक है। 2021 का चुनाव पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक निवेश था, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बावजूद जीत न मिलना, भाजपा के लिए एक अधूरी कहानी बन गया। ऐसे में अगर 2026 में भाजपा सत्ता हासिल करती है, तो इसे सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि 2021 की हार का राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिशोध माना जाएगा। यह जीत भाजपा के लिए पूर्वी भारत में अपने विस्तार को वैधता देने वाली होगी। एक ऐसा क्षेत्र, जहां वह अब तक सीमित प्रभाव ही बना पाई थी। हालांकि, ममता बनर्जी की सामाजिक योजनाएं और 'बंगाली अस्मिता' का नैरेटिव अब भी मजबूत है, जो भाजपा के विस्तार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन असली सवाल है कि क्या यह 'बदलाव' होगा? बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वर्ग और संस्कृति पर आधारित रही। ममता बनर्जी ने इसे वेलफेयर और क्षेत्रीय पहचान के साथ जोड़ा। भाजपा इसे 'पहचान-आधारित राष्ट्रवाद' और 'विकास' की दिशा में ले जाना चाहती है। यह टकराव सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधाराओं का है। तृणमूल सरकार पर "कट मनी", भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों के आरोप लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं और ग्रामीण

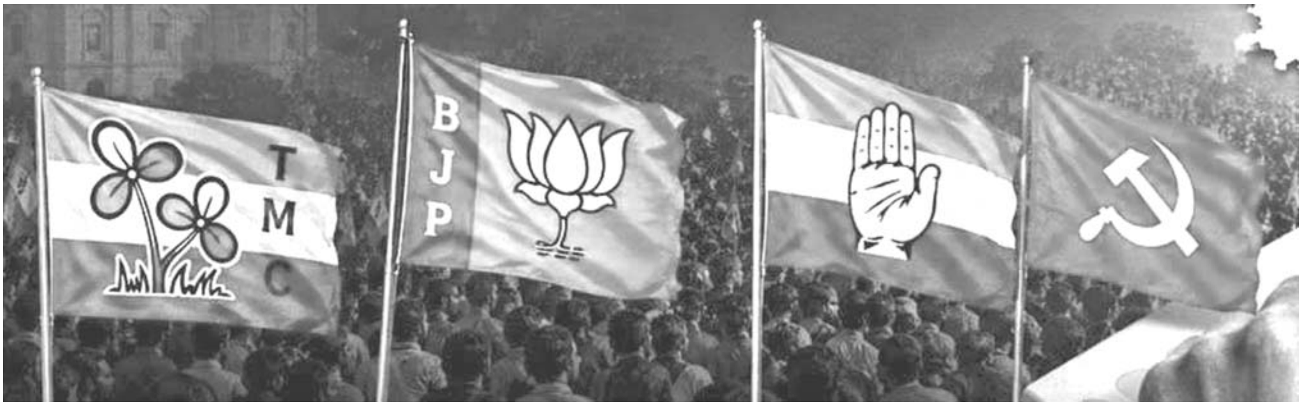

वर्गों में मजबूत समर्थन भी बनाया है। यानी, यह चुनाव "एंटी-इन्कम्बेंसी बनाम वेलफेयर लॉयल्टी" का संतुलन भी होगा। वही उच्च मतदान और मतदाता सूची को लेकर विवाद जैसे मुद्दे चुनाव को और जटिल बना सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का आधार मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण समर्थन है। भाजपा का उभार हिंदू ध्रुवीकरण, मटुआ और अन्य समुदायों में पैठ का होना है। अगर भाजपा जीतती है, तो यह सिर्फ सरकार बदलना नहीं होगा, यह बंगाल के सामाजिक गठजोड़ का पुनर्गठन होगा। साथ ही बता दें कि ममता बनर्जी की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ "बंगाली पहचान" रहा है। भाजपा इसके मुकाबले एक व्यापक राष्ट्रीय नैरेटिव पेश करती है। इसलिए 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि इस सवाल का भी है कि क्या बंगाल अपनी क्षेत्रीय पहचान को प्राथमिकता देगा या राष्ट्रीय राजनीति के साथ खुद को और जोड़ लेगा? दिलचस्प बात यह है कि बंगाल की राजनीति अब एक तीसरे चरण में प्रवेश करती दिख रही है। वामपंथ का वर्ग आधारित मॉडल, तृणमूल का वेलफेयर-आधारित क्षेत्रीय मॉडल, और अब भाजपा का पहचान-आधारित राष्ट्रीय मॉडल। 2026 का चुनाव तय कर सकता है कि इनमें से कौन सा मॉडल टिकाऊ साबित होता है। अगर ममता बनर्जी हारती हैं, तो भाजपा के लिए यह निश्चित रूप से "बदला" होगा, 2021 की हार का जवाब और पूर्वी भारत में वैचारिक विस्तार की बड़ी जीत। लेकिन बंगाल के लिए यह "बदलाव" तभी होगा, जब सत्ता के साथ राजनीतिक संस्कृति भी बदले। हिंसा, ध्रुवीकरण और प्रशासनिक ढांचे में सुधार आए। वरना, इतिहास बताता है कि यहां सत्ता बदलती है, लेकिन राजनीति की आत्मा धीरे-धीरे ही बदलती है। बंगाल में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता किसके पास होगी। 2026 का असली सवाल यह है, क्या यहां सिर्फ सरकार बदलेगी, या राजनीति की दिशा भी?

बहरहाल, चुनाव आयोग ने 91 लाख नाम हटाए हैं। वो भी अपने आप में एक बड़ा विवाद है। टीएमसी ने अपने पक्के वोटर्स को रोकने और एक बड़ी साजिश और वोटर दमन कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि डुप्लीकेट और माइग्रेटेड लोग थे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठे हैं। 92.87% के रिकॉर्ड मतदान के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर नामों को हटाया जाना। इसका सर्वे करने वालों के गणित को उलझाएगा। अगर ये हटे हुए नाम टीएमसी के मजबूत गढ़ों से थे तो इसका सीधा असर सीटों के समीकरण पर पड़ सकता है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को डराया। चुनावी हिंसा पुराने चुनावों की तुलना में कम रही। लेकिन डर का माहौल और मशीनी सुधारों का असर क्या होगा यह कोई नहीं जानता और जब जमीन की हकीकत परतों में छुपी हो, डाटा का आधार संदिग्ध हो तो एग्जिट पोल के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना सच कहें तो जुआ खेलने जैसा होता है और इसीलिए अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते, वो कहानी का ट्रेलर होते हैं। बंगाल वो जगह है जहां क्लाइमेट हमेशा ट्रेलर से आगे निकलता है, अलग निकलता है। आज स्क्रीन पर जो आंकड़े चमक रहे हैं वो शायद आपको एक दिशा दिखा रहे हो लेकिन जमीन पर जो खामोशी है वो असली फैसला लिख रही है। 2021 में बड़े दावे थे, ग्राफीक चमकदार थे लेकिन जब मतपेटी खुली तो सारा गणित बिखर गया। इस बार भी तस्वीर वैसी धुंधली सी लग रही है। एक तरफ डाटा, दूसरी तरफ हकीकत और बीच में खड़ा वो साइलेंट वोटर जो शायद इस सर्वे का हिस्सा नहीं लेकिन इतिहास लिखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल का चुनाव परिणामों से पहले बारूद के ढ़ेर पर है। इसलिए जो एग्जिट पोल के नंबर हैं, हम तो यही कहेंगे उन्हें आप आखिरी सच मत मानिए। क्योंकि लोकतंत्र में फैसला टीवी स्टूडियो में नहीं बल्कि वोटिंग बूथ पर होता है। असली ताकत उस उंगली में लगी स्याही में होती है ना कि स्क्रीन पर दौड़ते पर्सेंटेज पर। इसलिए 4 मई को सिर्फ सरकार नहीं तय होगी, यह तय होगा कि सच किसके साथ था और अगर बंगाल की राजनीति को सच में समझना है तो यह जरूर जानते होंगे आप कि यहां खेल आखिरी गेंद पलटा खेला होता है। जब पलटता है तो अनुमान छोटे होते हैं तो अनुमान तो छोटे होंगे। आप किसके वाले होंगे? बीजेपी वाले के होंगे, टीएमसी वाले के होंगे? यह 4 तारीख को पता चलेगा।

AMU Nigerian Student's '3 Idiots'-Style Hindi Speech Goes Viral

A video of an African student from Aligarh Muslim University is going viral on social media, thanks to his hilarious Hindi speech delivered in the style of a popular Bollywood character. The student, Ayuba, who is contesting for the post of secretary at Nadeem Tarin (NT) Hall, won over the audience with his confident and entertaining address. His speech, delivered entirely in Hindi, not only impressed fellow students but has also gained widespread attention online.

Speech Inspired by '3 Idiots'

The incident took place during a cultural event held on Tuesday evening at the university. Ayuba took the stage to present his election speech and chose a unique approach—he delivered it in the style of Chatur Ramalingam, the iconic character from the film 3 Idiots. His exaggerated expressions, comic timing, and fluent Hindi left the audience in splits, with many comparing him directly to the beloved movie character.

Promises That Stole the Show

During his speech, Ayuba made a series of bold and humorous promises to students. He said that if elected secretary, he would arrange facilities like air conditioning, washing machines, and even tea served three times a day. Adding to the fun, he jokingly promised to introduce a metro service for students commuting to and from the university—drawing loud cheers from the crowd.

Hall Echoes with Cheers

As Ayuba walked onto the stage, chants of "Ayuba! Ayuba!" filled the hall. Throughout his speech, students responded with enthusiastic applause and laughter. By the end, the venue resonated with slogans of "Ayuba Zindabad," reflecting the excitement and admiration among students. His confidence, humor, and unique style have earned him praise both on campus and across social media, where the video continues to circulate widely with memes and positive reactions.

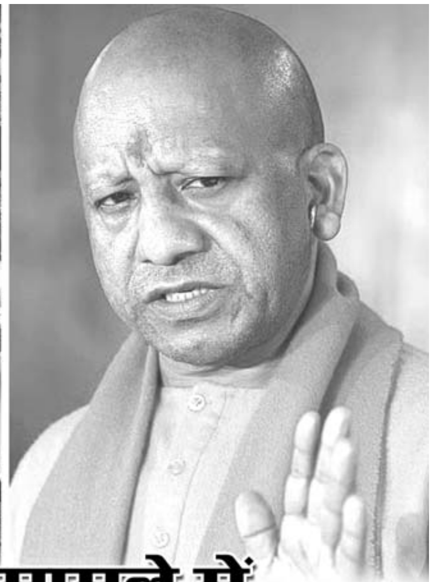

महिलाओं के सम्मान के मामले में योगी से काफी पीछे खड़े हैं अखिलेश

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)

भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ वाले महिला वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी की नजर लग गई है. पीडीए-पीडीए करते-करते सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश की उन महिलाओं को लुभाने में लग गए हैं, जो अखिलेश यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा डरी सहमी रहती थी. इसी को मुद्दा बनाकर 2017 में बीजेपी ने यूपी में सत्ता हासिल की थी. इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगीराज में महिलाएं अपने आप को समाजवादी सरकार के समय से ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं. इस बात का प्रमाण है भाजपा को मिलने वाला महिलाओं का वोट. महिला वोटर खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं, इसकी सबसे बड़ी समाजवादी सरकार के समय महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार. खैर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. अब अखिलेश यादव को महिलाओं के सम्मान की चिंता सताने लगी है. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर जब महिलाओं का सम्मान समारोह शुरू हुआ तो माहौल एकदम अलग था। अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली सैकड़ों महिलाओं को माला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने साफ कहा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनी तो 'नारी समृद्धि सम्मान योजना' शुरू होगी और इसके तहत गरीब परिवार की हर महिला को सालाना 40 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। साथ ही पुरानी समाजवादी पेंशन योजना को भी नई रूप में बहाल किया जाएगा। यह घोषणा महज कोई वादा नहीं बल्कि सपा की नई चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है जिससे आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को लक्ष्य बनाया गया है। वैसे बता दे इस तरह के दावे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में भी कर चुके हैं लेकिन महिला मतदाताओं ने उन पर विश्वास नहीं किया. दरअसल, अखिलेश यादव पिछले कई सालों से सत्ता वापसी की कोशिश में लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 के लिए उन्होंने उस फॉर्मूले में एक और अक्षर जोड़ दिया है। वह है 'ए' यानी आधी आबादी। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि पीडीए के साथ 'ए' को जोड़कर महिला सशक्तिकरण को चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पुरानी योजनाओं का भी जिक्र किया। 1090 हेल्पलाइन हो या मुलायम सिंह यादव कन्या विद्याधन योजना और रानी लक्ष्मीबाई योजना, इन सबको याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सपा हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने यह भी कहा कि

किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से तय होती है। अगर स्त्रियों की स्थिति की जानकारी हो जाए तो पूरे समाज की तस्वीर साफ हो जाती है।

कार्यक्रम का नाम रखा गया था मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान समारोह। मूर्ति देवी अखिलेश यादव की दादी और मुलायम सिंह यादव की मां थीं जिन्होंने मुलायम सिंह को सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का संस्कार दिया। वहीं मालती देवी मुलायम सिंह की पत्नी और अखिलेश की मां थीं जिन्होंने घर संभालकर पति को राजनीति के लिए पूरी आजादी दी। अखिलेश ने इन दोनों विभूतियों को याद करते हुए कहा कि इन्हीं संस्कारों के चलते वह आज इस मुकाम पर हैं, लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं का सम्मान करने के लिए उन्हें ऐसी कोई वीरांगना या सामाजिक आंदोलन चलाने वाली क्यों नहीं देखी जो उसके परिवार से इतर हो. सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस मौके पर कहा कि देश को आगे बढ़ना है तो महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने चिंता जताई कि नई पीढ़ी की बेटियां कुछ पीछे छूटती जा रही हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। अगर वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं

तो सत्ता परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। उन्होंने डायल 100 की पुरानी व्यवस्था का जिक्र करते हुए बताया

कि उन्होंने जान बूझकर वहां महिलाओं को रखा था क्योंकि वे दुख और तकलीफ को बेहतर समझती हैं। आने वाले समय में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर नई योजना लाकर महिलाओं को और सम्मान दिया जाएगा।

बहरहाल इस सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने अखिलेश सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को बड़ा मुद्दा बनाया था। तब एंटी रोमियो स्क्वायड जैसी पहल के साथ योगी सरकार ने इस वर्ग का विश्वास जीता। पिछले सालों में एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर जैसी नीतियों ने अपराधियों पर लगाम लगाई और महिलाओं को भयमुक्त माहौल देने का दावा किया गया। लेकिन अखिलेश अब कह रहे हैं कि मौजूदा समय में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर और दूसरे जिलों में घट रही घटनाओं का भी जिक्र किया जहां पुलिस पर दबाव का आरोप लगाया। उनका तर्क है कि आर्थिक मदद के साथ सुरक्षा का माहौल भी जरूरी है और यही कमी पूरी करने के लिए नारी समृद्धि योजना लाई जा रही है।

इस घोषणा का असर देखने के लिए बिहार का उदाहरण सामने है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को 10 हजार रुपये का कारोबार शुरू करने के लिए मदद देने का ऐलान किया। राशि सीधे खातों में पहुंची और महिला वोट बैंक ने एनडीए को बड़ा समर्थन दिया। यूपी में भी योगी सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं लेकिन अखिलेश ने सीधे नकद 40 हजार रुपये सालाना देने का वादा कर बड़ा दांव खेला है। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि सपा शासन में महिलाएं सुरक्षित रहीं और अब आर्थिक मजबूती से वे और मजबूत होंगी। उनका दावा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए महिलाएं सपा के साथ तेजी से जुड़ रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का मतलब ही

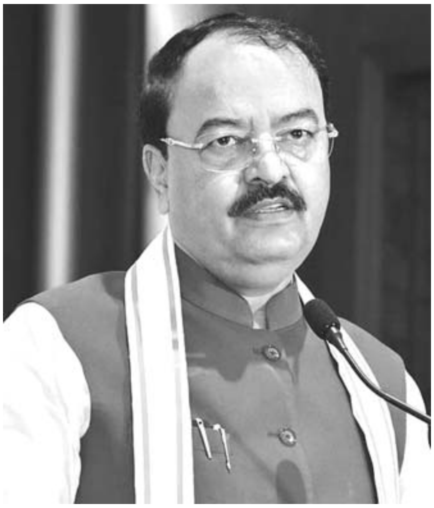

महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से लेकर 2022 तक हर चुनाव में आधी आबादी ने सपा को उखाड़ फेंका। 2024 में कुछ सीटें ज्यादा जीतने का श्रेय धोखे को दिया और कहा कि 2027 में सपा का पूरा सफाया होगा। मौर्य ने आगे कहा कि कोई अपना सुहाग संतान या राखी खतरे में नहीं डालेगा। सपा के पास गुंडे, माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज है। इसलिए सपा उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का हाल वही है जो सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उनके शासन में बहन बेटियां सहमी हुई थीं और नारा लगता था देख सपाई बिटिया घबराई। बहू बेटियों की आबरू लूटी जाती थी और निकलना दूभर था। वे मुंबई से डांस करने वालियां बुलाते थे और अब महिला सम्मान की बात करते हैं। पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

यह विवाद यूपी की राजनीति को और तेज कर रहा है। महिला वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहा है लेकिन सिर्फ आर्थिक वादा काफी नहीं होता। उनके प्रति नेताओं का व्यवहार भी अहम होता है। सपा को अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने के लिए और मेहनत करनी होगी। वहीं भाजपा अपनी कानून व्यवस्था और विकास की कहानी को और मजबूत करके पेश कर रही है। अखिलेश की यह योजना अगर लागू होती है तो लाखों गरीब महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। लेकिन बजट का सवाल भी उठेगा। यूपी में करोड़ों महिलाएं हैं और

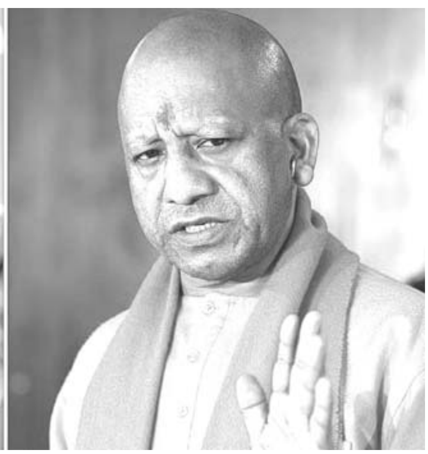

गरीब परिवारों को टारगेट करने पर भी खर्च बड़ा होगा। फिर भी राजनीतिक तौर पर यह दांव सपा को नया जोश दे सकता है। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगे भी बेहतर योजनाएं लाई जाएंगी। हर बच्ची युवती और नारी को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाई जाएगी। उन्होंने सपा के संकल्प को दोहराया कि प्रदेश की संपूर्ण उन्नति तभी संभव है जब महिलाएं मजबूत हों। इस बीच ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी दलों ने भी कटाक्ष किया है कि 'ना नौ मन गेहूं होई ना राधा नाचेगी'। लेकिन सपा का फोकस साफ है। वह महिला वोट को जोड़कर 2027 में वापसी का सपना देख रही है।

अब सवाल यह है कि यह वादा जमीनी स्तर पर कितना असरदार साबित होगा। महिलाएं न सिर्फ आर्थिक मदद चाहती हैं बल्कि सुरक्षा सम्मान और बेटियों की बेहतर शिक्षा भी चाहती हैं। सपा ने इन सबको जोड़ने की कोशिश की है। भाजपा की ओर से भी महिलाओं के लिए योजनाएं जारी हैं लेकिन सपा का यह सीधा नकद हस्तांतरण वाला मॉडल नया है। बिहार में कामयाब रहा तो यूपी में भी असर दिख सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा भारी पड़ता है। 2017 में यही मुद्दा सपा की हार का बड़ा कारण बना था। अब 2027 में दोनों पार्टियां इस मोर्चे पर आमने सामने हैं। कार्यक्रम में सम्मानित महिलाओं में खेल शिक्षा चिकित्सा पर्यावरण और किसान क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल थीं। यह दिखाता है कि सपा हर क्षेत्र की महिलाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर सत्ता आई तो पहले से बेहतर काम करेंगे। उनकी पार्टी का दावा है कि महिलाएं अब बदलाव चाहती हैं और वोट के जरिए वह बदलाव लाएंगी। दूसरी तरफ भाजपा का तर्क है कि सपा का राजनीतिक सूर्य अस्त हो चुका है और 2047 तक भी उम्मीद नहीं। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह महिला केंद्रित हो गई है। अखिलेश यादव का यह दांव 2027 के चुनावी मैदान को और रोचक बना रहा है। देखना होगा कि महिला वोट बैंक किसके पक्ष में झुकता है। क्या 40 हजार रुपये का वादा पुरानी यादों को मिटा पाएगा या कानून व्यवस्था की बात फिर भारी पड़ेगी। फिलहाल राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और दोनों पक्ष अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूपी की महिलाएं इस बार तय करेंगी कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए। ●

खेड़ा के आरोपों पर भड़के सीएम हिमंत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर असम पुलिस की तलाशी के बाद सियासी घमासान मच गया है। हालांकि तलाशी के दौरान खेड़ा अपने घर में नहीं मिले। शर्मा ने अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि पुलिस उन्हें पाताल से भी खोज निकालेगी। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि असम सरकार इसे कानूनी कार्रवाई बता रही है।

इस बयान से साफ है कि असम सरकार इस मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री शर्मा ने केवल पवन खेड़ा पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी इस मामले में घसीटा है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में राहुल गांधी से भी इस संबंध में कड़ी पूछताछ की जा सकती है। हिमंत ने कहा कि कोई भी आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि राहुल गांधी ने ही उन्हें ये दस्तावेज दिए हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह की झूठी जानकारी के आधार पर उनकी पत्नी के कई पासपोर्ट होने और दुबई में संपत्तियां होने का आरोप गढ़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान असम चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

विदित हो कि यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, जिसे राज्य में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां के खिलाफ कुछ दस्तावेज भी पेश किए। शर्मा दंपति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे झूठा एवं मनगढंत बताया था। रिंकी भुइयां शर्मा ने इस मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (निजी सुरक्षा के अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पहुंची। सरमा ने कहा कि पवन खेड़ा ने जो कागज पेश किए हैं, वे केवल राजनीति से

प्रेरित हैं और इसके पीछे की असली पटकथा राहुल गांधी ने लिखी है। वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे साथी पवन खेड़ा को जनहित में बुनियादी सवाल पूछने के कारण गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पूरे तंत्र को तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री विचलित, हताश और घबराए हुए हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस केस में जो होगा, उसे देखेंगे। कोई डरता नहीं है। हमने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के तंग करने के तरीके देखे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कोई भी प्रवक्ता यदि कुछ कहता है तो वह अपने मन से कुछ नहीं बोलता बल्कि पार्टी की ओर से बोलता है। अगर किसी प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर होती है तो यह गैरकानूनी है।

बहरहाल, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के मामले में उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी गई थी। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने खेड़ा और अन्य को नोटिस जारी कर तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली असम सरकार की याचिका पर उनका जवाब मांगा है। असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि असम में दर्ज एक मामले में जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में खेड़ा का आवेदन करना प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है और यह अपनी सुविधा के हिसाब से अनुकूल मंच चुनने का मामला प्रतीत होता है। याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक रहेगी। पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तारीख तय की है। गौरतलब है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को खेड़ा को कुछ शर्तों के साथ एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी थी। उन्हें संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।

Doctors Remove 3 Inch Live Fish from Toddler's Throat in Rare Surgery in Indore

In a remarkable medical feat, doctors at Indore's Maharaja Yeshwantrao Hospital (MYH), one of the largest government hospitals in Madhya Pradesh, successfully removed a 3-inch live fish from the throat of a one-year-old child, saving his life.

How the Incident Happened

The incident occurred while the child's family was cleaning a home aquarium. During the process, the child's elder sibling was holding a fish. The one-year-old, who was playing nearby, accidentally put the live fish into his mouth. The fish quickly slipped into the back of his throat (larynx) and became lodged. When the child was brought to the hospital, his condition was critical. The fish blocking his throat made it impossible for him to breathe. He was bleeding continuously from the mouth, his body had started turning blue due to lack of oxygen, and he was unable to even cry.

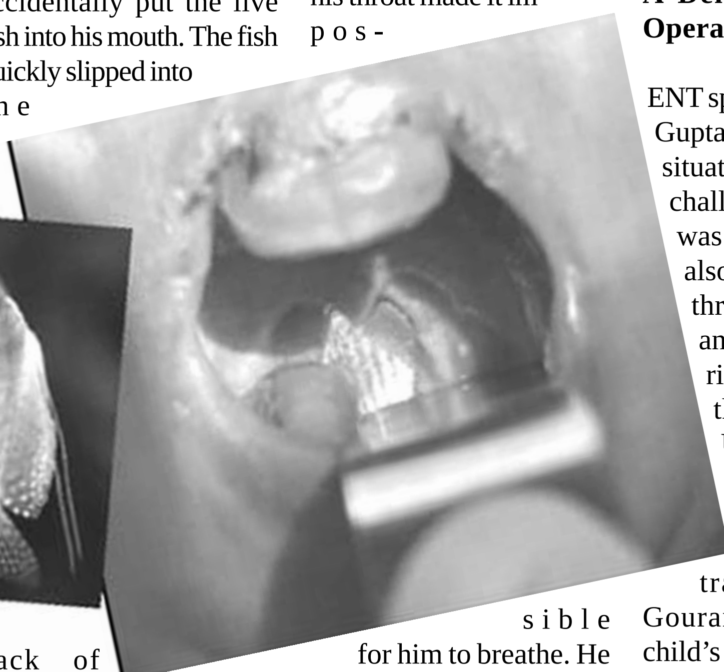

A Delicate and Risky Operation

A team led by ENT specialist Dr. Yamini Gupta acted swiftly. The situation was extremely challenging as the fish was not only long but also moving inside the throat. Its sharp fins and gills posed a serious risk of tearing the child's airway. Using a careful endoscopic procedure, doctors successfully extracted the live Gourami fish from the child's throat. The child is now stable, recovering well, and is expected to be discharged from the hospital soon.

● डॉ.ब्रह्मदीप अलूने

देश में नक्सलवाद के समाप्त होने की घोषणा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है,इससे देश के पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर गहरें प्रभाव पड़ने और समग्र विकास से जुड़ने की उम्मीदें बढ़ गई है। अब देश के बड़े क्षेत्रों में आम नागरिक भयमुक्त जीवन जी सकेंगे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच संघर्ष के कारण जो अस्थिरता थी,वह खत्म होगी और लोग शिक्षा,स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। सड़क,बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दूर-दराज के गांवों तक पहुंचेंगी और शासन की प्रभावी पहुंच दूरस्थ क्षेत्रों में सुनिश्चित होगी। पिछले कई दशकों से भारत में नक्सलवाद एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा खतरा था,जिसने छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बड़े आदिवासी क्षेत्रों को प्रभावित किया। यह केवल सुरक्षा बलों पर हमलों तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रशासनिक ढांचे को चुनौती देता था। बस्तर जैसे क्षेत्रों में नक्सलियों ने समानांतर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। विकास कार्य बाधित हुए, आदिवासी समाज भय और असुरक्षा में जीता रहा। नक्सलवाद ने लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता को गहराई से प्रभावित किया, जिससे यह देश के लिए एक

दीर्घकालिक और जटिल खतरा बन गया था। अमित शाह देश के पहले ऐसे गृहमंत्री रहे जिन्होंने बेखौफ नक्सली इलाकों में जाकर सुरक्षाबलों का हौंसला बढ़ाया और नक्सलियों को चुनौती देकर उनकी समय सीमा तय कर दी थी।

नक्सलियों ने लंबे समय तक आदिवासी क्षेत्रों में भय और भ्रम का माहौल बनाकर अपनी पकड़ मजबूत की थी। बस्तर जैसे इलाकों में उन्होंने स्थानीय लोगों को शासन के खिलाफ उकसाया और सरकारी योजनाओं से दूर रहने के लिए दबाव बनाया। इससे आदिवासी समाज विकास की मुख्यधारा से कटता गया। डर और असुरक्षा के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई। कई जगह नक्सलियों ने ठेकेदारों,शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों को निशाना बनाया, जिससे विकास कार्य बाधित हुए। इसके साथ ही, उन्होंने खुद को आदिवासियों का हितैषी बताकर उन्हें गुमराह किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आदिवासी इलाके लंबे समय तक पिछड़े रहे। आज जब नक्सल खत्म हुआ है तब इन क्षेत्रों में विकास की गति तेज होने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार की संभावनाएं बढ़ी हैं। अब आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। उनकी जमीन, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। निवेश और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र की प्राकृतिक संपदाओं का संतुलित उपयोग संभव होगा। नक्सलवाद का खत्म होना शांति, विश्वास और समावेशी विकास की स्थापना का प्रतीक होगा,जहां राज्य और समाज के बीच विश्वास बहाल होगा और लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत बनेगा।

भारत में नक्सलवाद रेड कॉरिडोर के रूप में फैले कुछ राज्यों और उनके संवेदनशील जिलों में कई वर्षों तक केंद्रित रहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जैसे जिलों

में कई वर्षों तक नक्सलियों का आतंक रहा, इसका नतीजा यह हुआ की खनिज संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ गया। झारखंड का लातेहार, पलामू, गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम के भी कमोबेश यही हाल रहे। ओडिशा तो खनिज और वन्य संसाधनों से भरपूर है, लेकिन मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और कालाहांडी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासियों को भूखमरी से जान से हाथ धोना पड़ा था। महाराष्ट्र का गडचिरोली,गोंदिया और चंद्रपुर हो या आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के भद्राद्री–कोठागुडेम और खम्मम जैसे जिले, नक्सलियों ने गरीब आदिवासियों को गुमराह कर अपनी समांतर सरकारें चलाई। इन क्षेत्रों में घने जंगल, दुर्गम क्षेत्र, सीमित प्रशासनिक पहुंच और आदिवासी बहुल आबादी नक्सलियों के लिए सुरक्षा कवच बन गई थी। यहां नक्सली संगठनों ने अपनी समानांतर संरचना खड़ी कर ली थी,जिसके चलते पुलिस, सुरक्षा बलों और सरकारी संस्थानों पर लगातार हमले होते रहे। इन हमलों का सबसे बड़ा असर स्थानीय आदिवासी समाज पर पड़ा। भय और असुरक्षा के माहौल में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्य बाधित रहे। कई गांव मुख्यधारा से कटे रहे और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के पीछे सुरक्षाबलों की सोशल पुलिसिंग एक महत्वपूर्ण कारण रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाबलों ने केवल सैन्य कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय आदिवासी समुदाय के साथ भरोसे का रिश्ता बनाने पर जोर दिया। कई बड़े नक्सली हमलों में अपने साथियों को खोने के बावजूद सुरक्षाबलों ने संयम बनाए रखा और संवाद की नीति नहीं छोड़ी। उन्होंने गांवों में चिकित्सा शिविर,शिक्षा सहायता,खेल गतिविधियां और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों के बीच अपनी सकारात्मक छवि बनाई। इससे आदिवासियों का विश्वास धीरे–धीरे बढ़ा और वे नक्सलियों के प्रभाव से बाहर आने लगे। सोशल पुलिसिंग का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि स्थानीय लोगों ने सुरक्षाबलों के साथ सहयोग करना शुरू किया,जिससे नक्सलियों की जानकारी जुटाना और उनकी गतिविधियों को सीमित करना आसान हुआ। इस प्रकार,सुरक्षा और संवेदनशीलता के संतुलन ने नक्सलवाद को कमजोर करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और कई उग्रवादियों के मारे जाने या आत्मसमर्पण करने की

घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि हिंसात्मक विचारधारा अब अपनी प्रासंगिकता खो चूकी है। सरकार की सुरक्षा रणनीतियों,विकास योजनाओं और स्थानीय सहयोग ने मिलकर इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया है। गडचिरोली और बस्तर जैसे क्षेत्रों में बदलाव यह दिखाता है कि जहां कभी बंदूक का असर था,वहां अब शासन और विकास की पहुंच बढ़ रही है। यह स्थिति देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है,इससे आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। जब हिंसा कम होती है,तो निवेश,शिक्षा,स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं,जिससे समाज में स्थिरता आती है। नक्सलवादियों को खत्म करने की घोषणा के साथ ही असल परीक्षा अब शुरू हो रही है। विकास और आदिवासी अधिकारों के बीच संतुलन सबसे बड़ी चुनौती होगी। आदिवासी क्षेत्रों में जल,जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं,बल्कि पहचान और जीवन का आधार हैं। सबसे चुनौती यह होगी कि सड़क,खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचे का विस्तार तो किया जाएं लेकिन इससे आदिवासी समुदायों का विस्थापन,सांस्कृतिक क्षरण या अधिकारों का हनन न हो। यदि विकास एकतरफा हुआ,तो असंतोष फिर जन्म ले सकता है। इसलिए भागीदारी आधारित विकास मॉडल पर धीरे धीरे आगे बढने की जरूरत होगी। जहां ग्राम सभाओं की सहमति, पारदर्शिता और स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता मिलना सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही,वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन,शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है। विकास तभी टिकाऊ होगा जब आदिवासी खुद उसके भागीदार बनें।

जाहिर है देश से नक्सलवाद के पूर्ण अंत को मानने से कहीं बेहतर है की इसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देंखे। स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि विकास, न्याय और विश्वास की प्रक्रिया लगातार जारी रहे। जिससे किसी भी प्रकार का असंतोष फिर से हिंसा का रूप न ले सके और नक्सल जैसी कोई विचारधारा फिर पनप ही न सकें।

हिन्दी पार्श्व गायन में अलग मुकाम हासिल करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। उन्होंने अपनी बहन तथा महान गायिका लता मंगेशकर की छाया में रहकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्हें शनिवार शाम सीने में संक्रमण और कमजोरी के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पोती जनाई भोसले ने यह जानकारी दी थी। उनके बेटे आनंद ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि लोग कल पूर्वाह्न 11 बजे लोअर परेल स्थित कासा ग्रांदे में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जहां वह रहती थीं। उनका अंतिम संस्कार कल शाम चार बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। भोसले ने परंपराओं को तोड़ते हुए सिनेमा में महिलाओं की आवाज को गहराई दी, चाहे वह 'हम इंतजार करेंगे' में विरह से भरी

मीना कुमारी हों या 'पिया तू अब तो आजा' में बेबाक और मदहोश हेलेन हों। अपने खास अंदाज– क्रीम–सुनहरे रंग की साड़ी, हीरों का जड़ाऊं नेक्लेस और बालों में सफेद गुलाब में सजी–धजी आशा ताई हाल ही में अर्जुन तेंदुलकर की शादी में नजर आई थीं जो उनका आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम माना जा रहा है।

☞ **1200 गाने किए रिकॉर्ड :–** आशा ने अपनी बहन लता के साथ मिलकर सात दशकों तक हिंदी पार्श्व गायन की दुनिया पर राज किया। बॉलीवुड में फिल्मी अभिनेत्रियों के लिए रिकॉर्ड किए गए लगभग हर फिल्मी गाने में उन्होंने अपनी आवाज दी। आठ दशकों से अधिक लंबे करियर में आशा ने अविश्वसनीय रूप से 12,000 गाने रिकॉर्ड किए। उनका पहला गाना 1943 में 10 वर्ष की आयु में मराठी फिल्म ''माझा बल'' के लिए था। उन्होंने 2010 के दशक के अंत तक और उसके बाद भी गायन जारी रखा, जिससे वह वैश्विक संगीत इतिहास में सबसे

लंबे समय तक गायन करने वाली गायिका बन गई। अदम्य, चुलबुली, जीवंत- उस कलाकार के लिए विशेषणों की कमी नहीं है, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय तक पूरे उत्साह के साथ गाया। आशा का विवाह 16 वर्ष की आयु में 1949 में गणपतराव भोसले से हुआ था और बाद में उन्होंने अपने सहयोगी एवं संगीतकार आर डी बर्मन से विवाह किया जिनके साथ उनकी लंबी और बेहद सफल संगीत यात्रा रही। ''मेरा कुछ सामान'' और ''दम मारो दम'' से लेकर ''चुरा लिया है तुमने'' और ''नहीं, नहीं, अभी नहीं'' तक उनके गीतों की यह श्रृंखला कैबरे, रोमांस, विरह और हर तरह के भावों से सजी रही।

☞ **पीएम मोदी ने ऐसे किया याद :-** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दशकों तक विस्तारित भोसले की असाधारण संगीतमय यात्रा ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक, आशा भोसले जी के निधन से मैं बेहद दुखी हूं। उनके साथ हुई बातचीत की यादें मेरे दिल में हमेशा बसी रहेंगी। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वह पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे।" दोनों बहनों आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच प्रतिद्वंद्विता को लेकर काफी अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन इसे साबित करने के लिए बहुत कम आधार थे। लता ने कबीर से कहा था कि यह कहना गलत है कि प्रतिस्पर्धा ने हमारे रिश्ते को खराब किया। हम बहनें हैं और पड़ोसी भी। हम एक-दूसरे से बात करते हैं और साथ खाना खाते हैं। अगर हममें से किसी को कोई परेशानी होती है, तो हम एक-दूसरे को बताते हैं। लता मंगेशकर गीतों को आवाज देने के लिए संगीतकार मदन मोहन की पहली पसंद थीं, जिन्हें मधुर संगीत और गजलों का उस्ताद माना जाता है, वहीं आशा भोसले भी इस शैली में उतनी ही निपुण थीं। फिल्म 'उमराव जान' की उनकी गजलें आज भी याद की जाती हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था।

भोसले के लोकप्रिय गीतों में 'अभी न जाओ छोड़ कर', 'इन आंखों की मस्ती', 'दिल चीज क्या है', 'पिया तू अब तो आजा', 'दुनिया में लोगों को' और 'जरा सा झूम लूं मैं' जैसे गाने शामिल हैं। उन्होंने पद्मिनी एवं वैजयंतीमाला जैसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों से लेकर मीना कुमारी, मधुबाला, जीनत अमान, काजोल और उर्मिला मातोंडकर सहित कई प्रमुख अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी। आशा ने 2023 में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दुबई में आयोजित एक विशेष संगीत कार्यक्रम 'आशा 90: लाइव इन कॉन्सर्ट' में प्रस्तुति दी थी। उनकी आवाज अंत तक गहन ठहराव, लचीलापन और ताजगी लिए रही। उन्होंने आखिरी बार गोरिलाज के एल्बम 'द माउनटेन' के लिए अपनी आवाज दी, जिसमें उन्होंने 'द शेडो लाइट' गीत गाया। यह गीत 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ था। आठ सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मीं आशा भोसले को अपनी बहन की तरह ही उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने संगीत की शिक्षा दी थी। संगीत मानो उनकी नियति में ही था। चार बहनों में लता, ऊषा और आशा पार्श्व गायिका बनीं जबकि मीना संगीतकार हैं। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीतकार हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित आशा भोसले एक सफल उद्यमी भी थीं। उन्होंने दुबई और ब्रिटेन में 'आशा' नाम से लोकप्रिय रेस्तरां संचालित किया। उन्हें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई अन्य संगीत सम्मानों से नवाजा गया।

140 Chickens Die Due to Loud DJ Music During Wedding Procession in UP

A bizarre incident has surfaced from Uttar Pradesh's Sultanpur, where a poultry farmer has alleged that loud DJ music played during a wedding procession led to the death of 140 chickens.

The complaint was filed by Sabir Ali, who claimed that the incident occurred when a wedding procession passed in front of his poultry farm on the night of April 25. The procession belonged to the family of a local resident, Babban Vishwakarma, whose daughter was getting married. The baraat had arrived from Ram Bhadra Purwa in the Kudwar area and included a DJ system playing music at high volume.

According to Sabir Ali, the procession passed his farm around 9:30 PM, and the extremely loud music caused panic among the birds. He alleged that the chickens were unable to withstand the high-decibel noise, leading to the sudden death of 140 birds. In his complaint to the police, Sabir described the sound as "extremely loud," stating, "The noise was so intense that the chickens got frightened and died."

Following the complaint, police registered a case against a DJ operator, Kavi Yadav, from Parsipur on the night of April 28. Authorities are currently investigating whether the sound system exceeded permissible noise limits at the time of the incident. Officials are also examining other possible factors to determine whether loud noise alone caused the deaths. Experts note that intense sound waves can trigger severe stress in birds and animals, and in extreme cases, may even lead to cardiac arrest.

फार्म IV (नियम 8 देखें)

01. प्रकाशन का स्थान	:- पटना
02. प्रकाशन की आवर्तिता	:- मासिक
03. मुद्रक का नाम	:- ब्रजेश मिश्र
क्या भारतीय नागरिक हैं?	:- हां
(अगर विदेशी हों, तो मूल देश का नाम)	:- लागू नहीं
पता	:- पूर्वी अशोक नगर रोड नं-14, कंकड़बाग पटना-800020 (बिहार)
04. प्रकाशक का नाम	:- ब्रजेश मिश्र
क्या भारतीय नागरिक हैं?	:- हां
(अगर विदेशी हों, तो मूल देश का नाम)	:- लागू नहीं
पता	:- पूर्वी अशोक नगर रोड नं- 14, कंकड़बाग पटना-800020 (बिहार)
05. संपादक का नाम	:- ब्रजेश मिश्र
क्या भारतीय नागरिक हैं?	:- हां
(अगर विदेशी हों, तो मूल देश का नाम)	:- लागू नहीं
पता	:- पूर्वी अशोक नगर रोड नं- 14, कंकड़बाग पटना-800020 (बिहार)
06. उन लोगों के नाम और पते जो समाचार पत्र के मालिक हों, या जिनके पास कुल पूंजी का एक फीसदी से अधिक हो	:- मालिक श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट पूर्वी अशोक नगर रोड नं- 14, कंकड़बाग पटना-800020 (बिहार)
07. कुल पूंजी में एक फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाली शेयरधारकों के नाम और पते	:- मालिक श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट पूर्वी अशोक नगर रोड नं- 14, कंकड़बाग पटना-800020 (बिहार)

मैं ब्रजेश मिश्र घोषणा करता हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा मेरी जानकारी और मान्यता के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर (ब्रजेश मिश्र)

दिनांक:- 5 अप्रैल 2026 प्रकाशक का हस्ताक्षर

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

☆ **प्रोबेट क्या होता है?**

प्रोबेट (प्रोबेट) एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी मृत व्यक्ति की वसीयत (विल) को अदालत द्वारा वैध और आखिरी इच्छा के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

❖ **प्रोबेट का मतलब :-** प्रोबेट अदालत द्वारा जारी एक सर्टिफिकेट/ऑर्डर होता है जो यह दिखाता है कि वसीयत सही तरीके से बनी है, वसीयतकर्ता की आखिरी इच्छा है और कानूनी रूप से वैध है। इसके बाद वसीयत में नामित एक्जीक्यूटर (निष्पादक) को अदालत की ओर से अधिकार मिलता है कि वह मृतक की संपत्ति को वसीयत के अनुसार बाँटे और प्रबंधित करे।

❖ **प्रोबेट क्यों जरूरी होता है? :-** बैंक, रजिस्ट्री ऑफिस या अन्य संस्थान अक्सर बिना प्रोबेट के वसीयत के आधार पर संपत्ति ट्रांसफर नहीं करते, खासकर जब संपत्ति बड़ी हो या विवाद की संभावना हो। प्रोबेट से भविष्य में उत्तराधिकारियों के बीच झगड़े कम होते हैं क्योंकि अदालत ने वसीयत की वैधता पहले ही साबित कर दी होती है।

❖ **भारत में कब प्रोबेट लेना जरूरी है? :-** मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के पुराने न्यायिक क्षेत्रों में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन वसीयतों के मामले में प्रोबेट अनिवार्य माना जाता है। अन्य जगहों पर प्रोबेट हमेशा अनिवार्य नहीं है, लेकिन बड़ी संपत्ति, विवाद या बैंक/रजिस्ट्रार की शर्त होने पर लेना सलाह दिया जाता है। भारत में प्रोबेट कब अनिवार्य होता है, यह मुख्य रूप से संपत्ति की जगह और वसीयतकर्ता के समुदाय पर निर्भर करता है :-

☞ **जहाँ प्रोबेट अनिवार्य माना जाता है :-** जब मृतक ने वसीयत बनाई हो और उसकी संपत्ति मुंबई, कोलकाता या चेन्नई के नगरपालिका क्षेत्रों में हो (इन्हें ष्प्रेसीडेंसी टाउनष कहा जाता है), तो प्रोबेट कानूनन अनिवार्य माना जाता है। यह अनिवार्यता खासकर हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदायों पर लागू होती है, जब वसीयत इन शहरों में स्थित संपत्ति के लिए बनाई गई हो।

☞ **अन्य स्थितियाँ जब प्रोबेट जरूरी हो जाता है :-** जब बैंक या कोई संस्थान संपत्ति ट्रांसफर करने से पहले प्रोबेट की मांग करता है (जैसे बड़ी रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट, जमीन/मकान आदि)। जब वसीयत पर परिवार में विवाद हो या होने की संभावना हो, तो अदालत की ओर से प्रोबेट लेना अनिवार्य न होते हुए भी जरूरी माना जाता है।

☞ **जहाँ प्रोबेट आम तौर पर अनिवार्य नही है :-** मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के बाहर बाकी जगहों पर सभी मामलों में प्रोबेट अनिवार्य नहीं है; वहाँ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रशासन पत्र से भी संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है। मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि के लिए अलग उत्तराधिकार कानून हैं, जहाँ प्रोबेट हमेशा अनिवार्य नहीं होता, बल्कि विशेष परिस्थितियों में लिया जाता है।

☆ **रिट कितने प्रकार के होते हैं?**

भारतीय संविधान के तहत मुख्य रूप से पाँच प्रकार की रिट (राइट्स) होती हैं, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं और अदालतों द्वारा जारी किए गए आदेश हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबीज कॉरपस), परमादेश (मैंडेमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) और अधिकार पृच्छा (क्वो-वारंटो). ये रिट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करती हैं।

❖ **पाँच मुख्य प्रकार की रिटें :-**

☞ **बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबीज कॉरपस) :-** किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने से बचाने के लिए, यह आदेश देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए ताकि हिरासत की वैधता की जाँच हो सके।

☞ **परमादेश (मैंडेमस) :-** यह एक सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है, जब वह ऐसा करने में विफल रहता है।

☞ **प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) :-** निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।

☞ **उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) :-** निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के अवैध या गलत आदेश को रद्द करने या मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

☞ **अधिकार पृच्छा (क्वो-वारंटो) :-** किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद को चुनौती देने के लिए जारी किया जाता है, यह पूछता है कि ष्किस अधिकार से?

❖ **अतिरिक्त जानकारी :-**

☞ **अनुच्छेद 32 (संविधान) :-** सुप्रीम कोर्ट को इन रिटों को जारी करने का अधिकार देता है, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है।

☞ **अनुच्छेद 226 (संविधान) :-** उच्च न्यायालयों को मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ये रिट जारी करने का अधिकार देता है।

आवश्यकता
अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....
बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका
केवल सच
और
केवल सच TIMES
को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।
योग्यता:-
जिला ब्यूरो
स्नातक उतीर्ण
प्रखंड संवाददाता
स्नातक/इंटर
पंचायत संवाददाता
स्नातक/इंटर/मैट्रिक
विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नातक/इंटर/मैट्रिक
संपर्क करें:-
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग
पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. — Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008